अर्थशास्त्र

मैक्रो इकॉनॉमिक्स (समष्टि अर्थशास्त्र)

समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। (राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी)

जनक - एडम स्मिथ

- ↓ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक
- ↳ "The wealth of Nation"

माइक्रो Economics (सूक्ष्म अर्थशास्त्र)

सूक्ष्म / व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाइयों और व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है।

जनक - जे. एम. कीन्स (इंग्लैंड)

↳ धन का सामान्य सिद्धांत

"आर्थिक गतिविधियों का संगठन"

- केंद्रीकृत योजनाबद्ध → सरकार
- बाजार स्तर पर → व्यक्ति की मुक्त अंतःक्रिया

अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार:

1. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था → सरकार के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है।
2. समाजवादी अर्थव्यवस्था → निजी क्षेत्र का कोई स्वामित्व नहीं है।
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था → दोनों (उदाहरण - भारत)

PARMAR SSC

	पूंजीवादी	समाजवादी	मिश्रित
1. स्वामित्व	व्यक्तिगत (US)	सार्वजनिक (रूस) (सरकार)	दोनो (भारत)
2. आर्थिक उद्देश्य/मकसद	लाभ	समाज कल्याण	दोनो
3. सरकार की भूमिका	कोई भूमिका नही	पूरी भूमिका	सीमित भूमिका
4. आय का वितरण	असमान	समान	कम असमान
5. आर्थिक स्वतंत्रता	पूरी स्वतंत्रता	स्वतंत्रता की कमी	

1991 : लाइसेंस राज → भुगतान का संतुलन

LPG → वैश्वीकरण
LPG → उदारीकरण, निजीकरण

सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं के बीच अंतर

निजी सामान → कार

प्रतिद्वंदिता

केवल एक व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करता है।

बहिष्कृत

व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी कार में बैठने से रोक सकता है।

सार्वजनिक → रोड (सड़क)

गैर-प्रतिद्वंदिता

सभी को संतुष्टि प्रदान करता है।

गैर-बहिष्कृत

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पुल का उपयोग कर सकता है।

PARMAR SSC

आमतौर पर, निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया।
(निजी कार कंपनी द्वारा निर्मित)

(सकारात्मक सीमांत लागत)

सामान्यतः सरकार द्वारा प्रदान किया गया। (सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक प्रावधान)

(शून्य सीमांत लागत)

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र :

1. प्राथमिक क्षेत्र
2. द्वितीयक क्षेत्र
3. तृतीयक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र : सीधे तौर पर पर्यावरण पर पे निर्भर।

कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन

इसमे संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिये संकेतित किया जाता है।

- अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी।

द्वितीयक क्षेत्र : अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादो को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है।

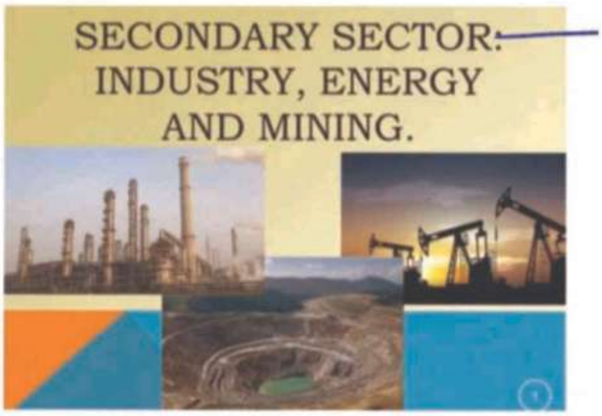

लोहा-इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स आदि

→ ब्लू कॉलर जॉब

→ देश की रीढ की हड्डी

PARMAR SSC

- इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है।
- द्वितीयक क्षेत्र को देश की रीढ़ कहा जाता है , यह देश के औद्योगीकरण में मदद करता है। उदा० - चीन
- भारत में इसका समुचित विकास नहीं हुआ है , हम सीधे तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गये हैं।

तृतीयक क्षेत्र : 'सेवा क्षेत्र'

इस क्षेत्रक मे विभिन्न प्रकार की सेवाओ का अध्ययन उत्पादन किया जाता है।
जैसे - बीमा , बैंकिंग , चिकित्सा , शिक्षा , पर्यटन आदि।

→ white coller jobs

→ प्रकृति में यह सदैव अमूर्त है।

→ हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च योगदान : तृतीयक क्षेत्र

→ प्राथमिक क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगो को रोजगार मिलता है, GDP में इसका योगदान सबसे कम (14.39% है)

→ द्वितीयक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 31.46% का योगदान देता है।

→ तृतीयक क्षेत्र में सबसे कम लोग कार्यरत हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान सबसे अधिक है (54.15%)

2011 जनगणना

	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
LFPR	54.6%	24.3%	21.1%
GDP मे %	14.39%	31.46%	54.15%

PARMAR SSC

चतुर्थातुक क्षेत्र : (चतुर्थक) यह सरकार, संस्कृति, पुस्तकालयों, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बौद्धिक गतिविधियो पर आधारित है।

→ Knowledge Sector

क्विनरी क्षेत्र : ऐसी सेवाएँ जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
(राजनैतिक, वरिष्ठ व्यापार कार्यकारी)

→ Gold coller job

→ तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है।

→ सबसे कम योगदान- प्राथमिक क्षेत्र

→ सबसे ज्यादा कार्यों मे संलग्न लोग- प्राथमिक क्षेत्रों मे

→ सबसे कम " " " - तृतीयक क्षेत्र

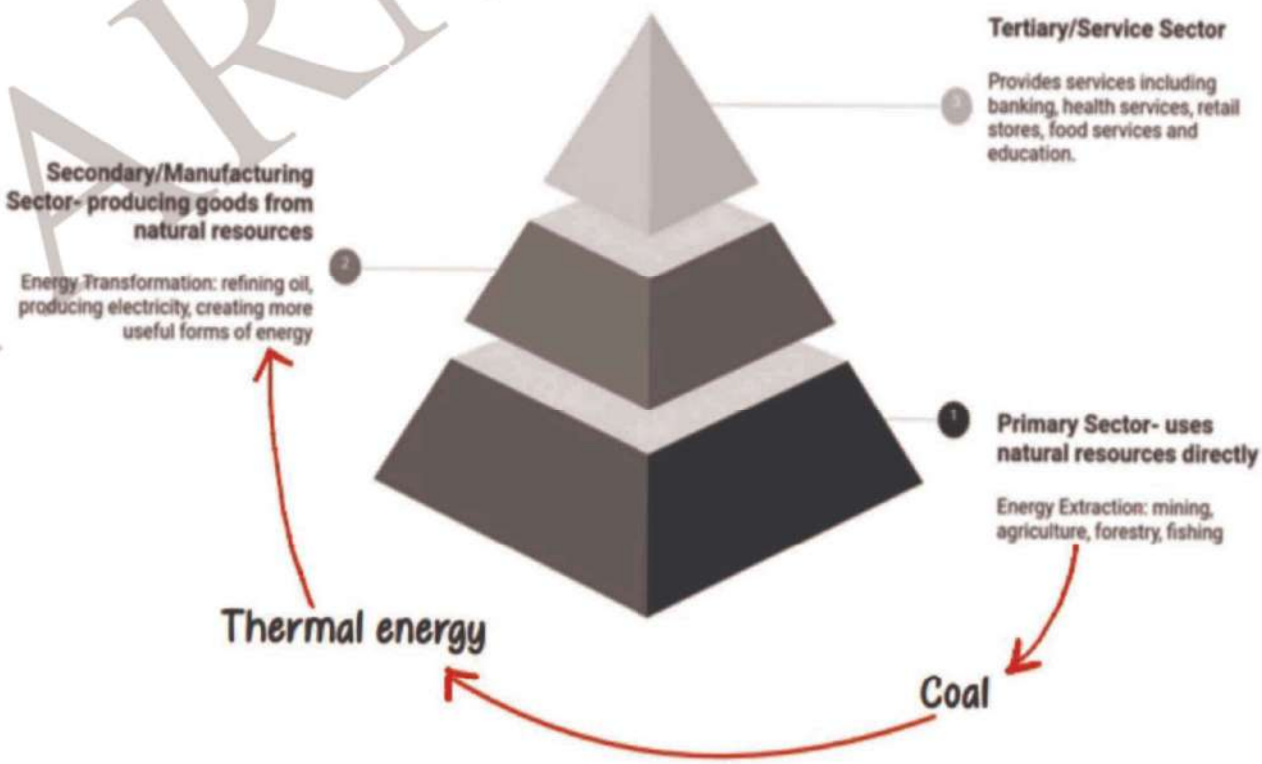

PARMAR SSC

सूक्ष्म अर्थशास्त्र

अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या :

↳ सीमित स्रोत

अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों का आवंटन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के एक विशेष संयोजन को जन्म देता है।

उपलब्ध कुल संसाधनों को कई अलग - अलग तरीकों से आवंटित करना संभव है, जिससे सभी संभावित वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न मिश्रण प्राप्त किए जा सकते हैं।

वह संकलन, जिसमें दिए गए संसाधनों की एक निश्चित मात्रा और प्रौद्योगिकी ज्ञान के एक निश्चित स्तर से उत्पादित की जा सकने वाली सभी संभावित वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन शामिल होते हैं, उसे अर्थव्यवस्था का **उत्पादन संभाव्यता समुच्चय** कहा जाता है।

उत्पादन संभावना सीमा वक्र

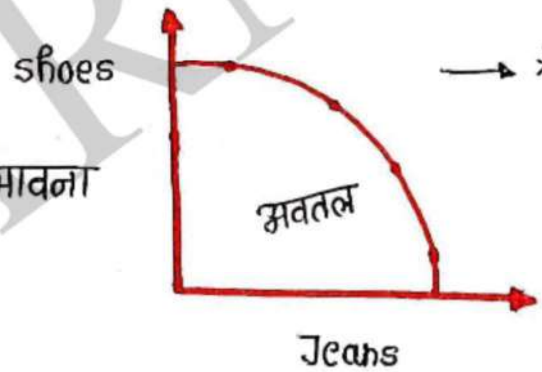

→ ऋणात्मक ढलान / नीचे की ओर

- वक्र पर - संसाधनों का पूर्ण उपयोग।
- नीचे की ओर - संसाधनों का कम उपयोग।
- ऊपर की ओर - उपलब्ध नहीं।

PARMAR SSC

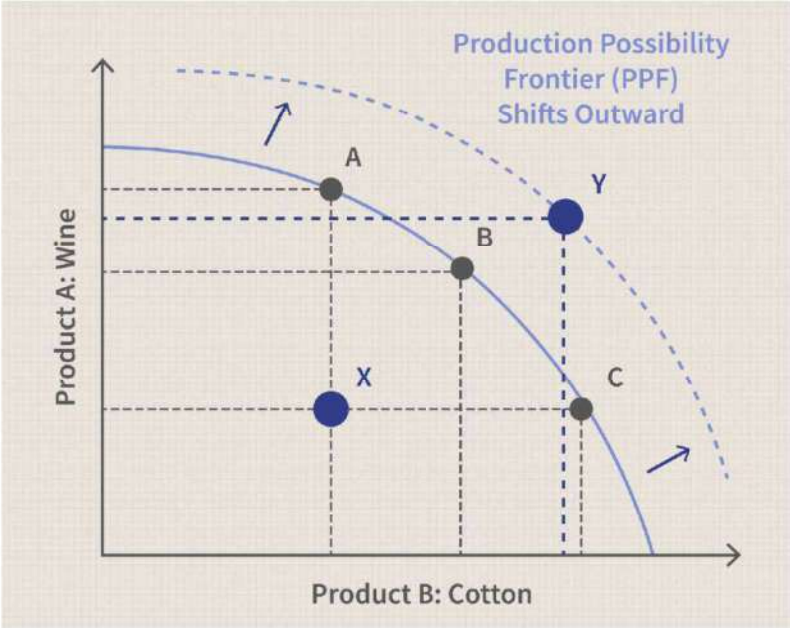

इस प्रकार, किसी एक वस्तु की थोड़ी अधिक मात्रा प्राप्त करने की हमेशा एक लागत होती है, जो दूसरी वस्तु की उस मात्रा के रूप में होती है जिसे त्यागना पड़ता है। इसे अवसर लागत कहा जाता है।

'मुफ्त वस्तुएं' (Free goods) वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कोई अवसर लागत नहीं होती, क्योंकि वे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं और दुर्लभ नहीं होतीं। इसका अर्थ है कि इन्हें प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वस्तु के उत्पादन का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके उदाहरणों में वायु, सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ जल शामिल हैं।

उपयोगिता (Utility)
- Cardinal → संख्या
- Ordinal

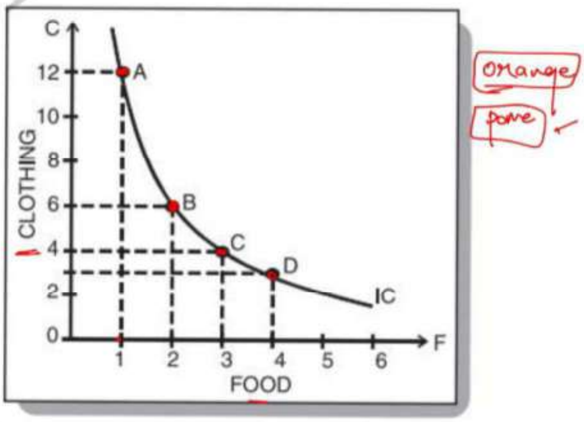

Fig. 1 : A Consumer's Indifference Curve

PARMAR SSC

सीमांत उपयोगिता : किसी अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतोष।

कुल उपयोगिता : किसी वस्तु की कुल उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल योग।

सीमांत उपयोगिता की घटती प्रवृत्ति का नियम :

किसी वस्तु की लगातार बढ़ती इकाइयों के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता (Marginal Utility) धीरे-धीरे घटता जाता है।

Example of Marginal Utility:

Jab tum Golgappa Khate ho to jaise jaise additional golgappa khate ho waise waise tumhe Anand ki Prapti hoti jati hai.

Each Next Golgappe me tumhe **Additional Satisfaction** Milta hai .

Aur Aakhiri me tum Papdi kha ke **Santust** ho jate ho

मांग और आपूर्ति :

मांग
- इच्छा / Eagerness
- औकात / Affordability / सामर्थ्य
- संतुष्टी / Satisfaction - Utility

PARMAR SSC

मांग वक्र / Demand Curve :

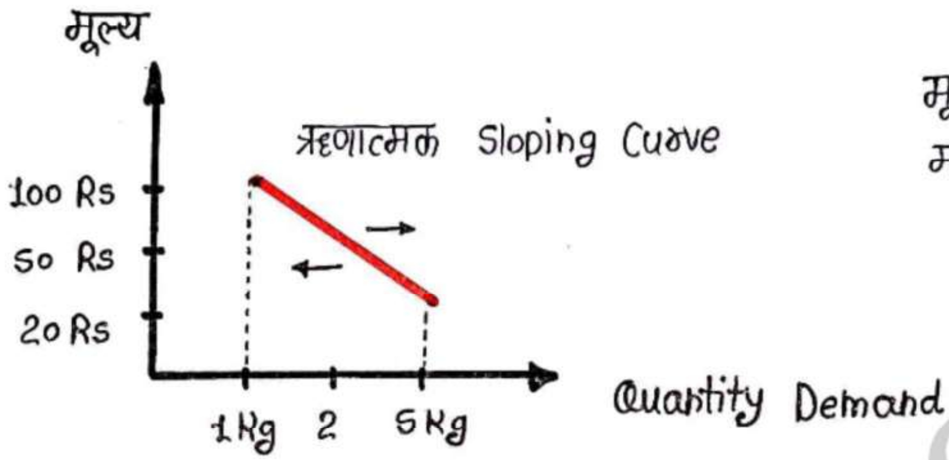

मूल्य
मांग } Inverse

Rightward → outward →

Leftward → Inward shift ←

अन्य फैक्टर constant :
वेतन / Income

वक्र मे गति (movement) और बदलाव (shift) :

↓ जब मूल्य में परिवर्तन करते है।

↓ जब मूल्य के अलावा परिवर्तन करते है। (आय, वरीयता, अन्य माल का मूल्य)

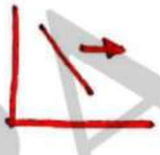

Rightward shift → जब मांग बढ़ जाती है।
दायीं ओर शिफ्ट

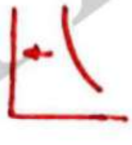

Leftward shift → जब मांग घट जाती है।
बायीं ओर शिफ्ट

अपवाद :

- गिफेन गुड्स / Giffen goods → गैर लक्जरी → अनाज, नमक ↑
- वेब्लेन गुड्स / Veblen goods → लक्जरी वस्तु
  ↑ (I-phone, audi) BMW

मूल्य ∝ मांग

PARMAR SSC

आपूर्ति वक्र / Supply Curve :

निर्माता की तरफ से / लाभदायक Profitability

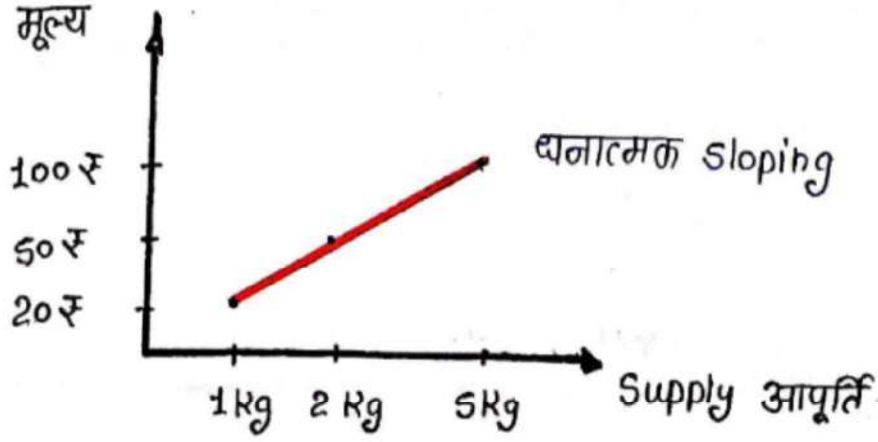

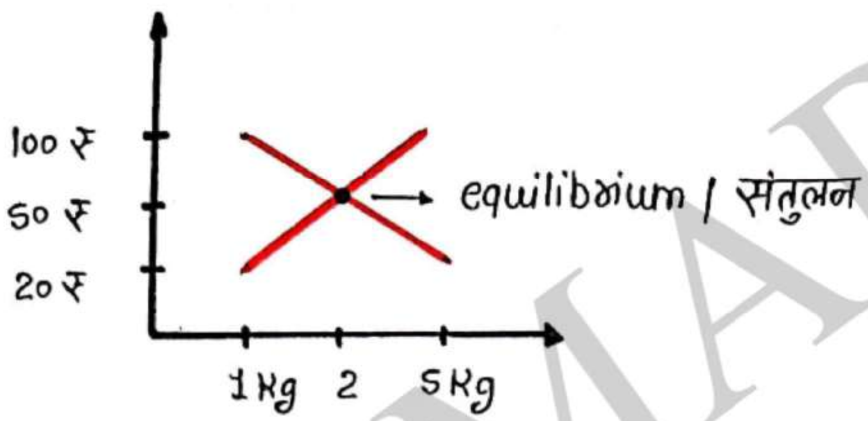

वस्तुयें संतुलन में मौजूद हैं।

यदि किसी भी एक कारक में बदलाव होता है तो संतुलन बदल जाता है।

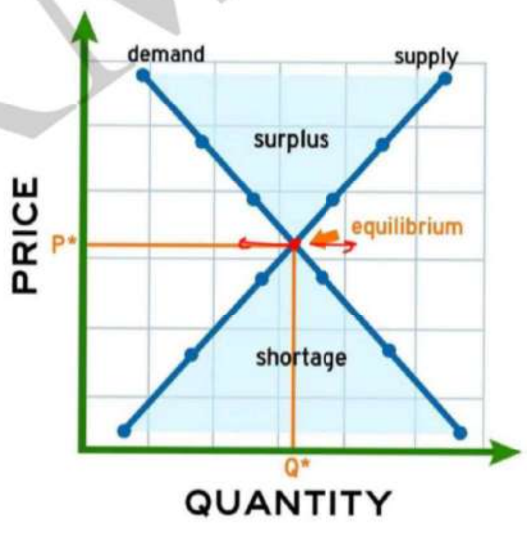

मूल्य लोच / Price Elasticity :

PARMAR SSC

मूल्य मे परिवर्तन → मांग मे परिवर्तन

आमतौर पर ऋणात्मक

$$\text{मूल्य लोच } (e_d) = -\frac{\text{मांग मे \% परिवर्तन}}{\text{मूल्य मे \% परिवर्तन}}$$

पूर्णतया लोचदार मांग / Perfectly elastic demand :

$e_d = \infty$

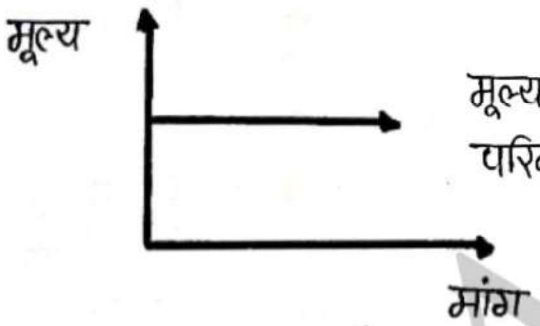

मूल्य में नगण्य / शून्य परिवर्तन मांग में बड़े परिवर्तन का कारण बनता है। (अनंत)

अपेक्षाकृत लोचदार मांग / Relatively elastic demand :

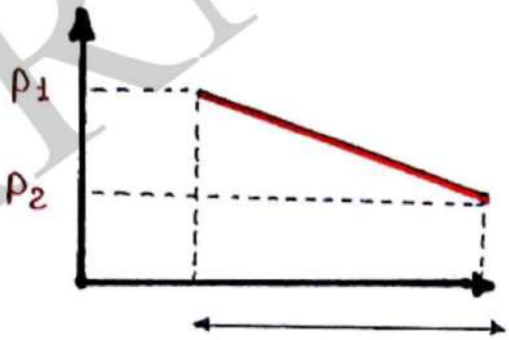

$e_d > 1$

कीमत में मामूली परिवर्तन से मांग में भारी बदलाव

PARMAR SSC

पूर्णतया वेलोचदार मांग / Perfectly Inelastic demand :

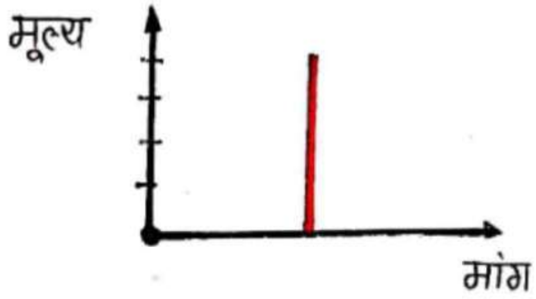

→ Vebleh goods

$e_d = 0$

- उद्ववधिर
- वेब्लेन माल
- कीमत में परिवर्तन होने पर उत्पाद की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता।

अपेक्षाकृत वेलोचदार मांग / Relatively enelastic demand :

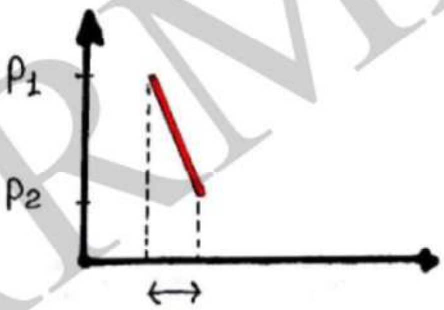

$e_d < 1$

कीमत में परिवर्तन से मात्रा मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होता है।

मांग की आय लोच / Income elasticity of demand :

आय में परिवर्तन & कुछ वस्तुओं की मांग के बीच संबंध

आय / Income	demand / मांग	
↑	↑	धनात्मक
↓	↓	ऋणात्मक

PARMAR SSC

Cross price elasticity:

x मूल्य ↑ ↓ मांग → y ↑ मांग

धनात्मक

लोगो द्वारा पैसा रखने के तीन उद्देश्य :

- Transaction motive — लेन-देन के उद्देश्य से
- Precautionary motive → Receipt खर्च, भविष्य
- Speculative Motive — सट्टा मकसद

Speculative Motive → जे एम कीन्स (पैसे की सट्टा मांग)

परिसंपत्ति की मांग / Speculative demand for money → पैसे को अपने पास रखना

1. ब्याज दर कम → Speculative demand High (उच्च)
2. ब्याज दर अधिक → Speculative demand less (कम)

बाजार के प्रकार

1. एकाधिकार : (Monopoly) केवल एक विक्रेता, Entry Barrier

   उदा० : भारतीय रेलवे

2. अल्पाधिकार बाजार : (Oligopoly market) कम संख्या मे आपूर्तिकर्ताओं का वर्चस्व

   अधिक खरीददार, No easy entry

   उदा० : टेलीकॉम सेक्टर (Jio, Airtel, VI), लैपटॉप

PARMAR SSC

3. **एकाधिकार प्रतियोगिता / Monopolistic competition:**

- बहुत विक्रेता, बहुत खरीददार उदा: टूथपेस्ट, कपड़े
- समान लेकिन थोड़े अलग उत्पाद

4. **पूर्ण प्रतियोगिता / Perfect competition:**

- बहुत विक्रेता, बहुत खरीददार
- सजातीय उत्पाद / homogenous product
  उदा०: Agricultural उत्पाद
- free entry / exit

PARMAR SSC

" राष्ट्रीय आय "

आय का चक्रीय प्रवाह

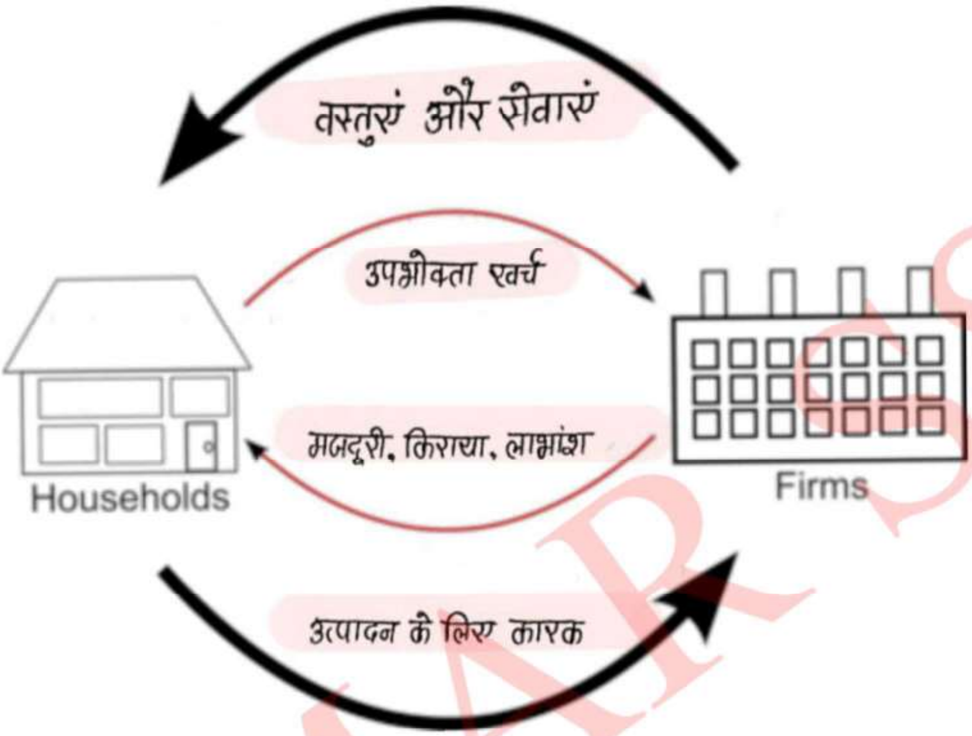

उत्पादन के कारक :

- भूमि → किराया
- श्रम → वेतन
- पूंजी → ब्याज
- उद्यमी → लाभ

} कारक भुगतान

GDP की गणना करने के तरीके :

1. **मूल्य / उत्पाद वर्धित विधि :** आउटपुट - इनपुट

Value added / Production method

PARMAR SSC

कपास → धागा मिल → कपड़ा → शर्ट

कपास	धागा मिल	कपड़ा	शर्ट	
₹100	₹200	₹400	₹800	
100₹	₹100	₹200	₹400	= ₹800

सकल मूल्य वर्धित (GVA)-

$$\sum GVA = GVA_1 + GVA_2$$

अंतिम माल

→ वह वस्तुएं जिन्हें आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती हैं। इन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में भी जाना जाता है और इनका उत्पादन अंतिम उपभोक्ता द्वारा सीधे उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है।

अंतिम माल → उपभोक्ता वस्तुएं / माल, पूंजीगत माल

मध्यवर्ती माल

→ मध्यवर्ती वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप मे संदर्भित किया जाता है जिनका उपयोग व्यवसायों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इन वस्तुओं को उत्पादक वस्तुओं के रूप में भी जाना जाता है।

चाय → आप (अंतिम), चायवाला (मध्यवर्ती)

उपभोक्ता वस्तुएं: वे वस्तुएं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण- घरेलू सामान, खाद्य & पेय पदार्थ, कपड़े आदि।

पूंजीगत माल: वे मूर्त संपत्तियां जिनका इस्तेमाल किसी कारोबार में उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण- मशीनरी, उपकरण, भवन, वाहन, कम्प्यूटर आदि।

PARMAR SSC

इन्वेंटरी : (संचय) किसी कंपनी द्वारा रखे गए वे सभी सामान, माल और सामग्री जिन्हें वह बाजार में बेचती है या उत्पादन में इस्तेमाल करती है।

नियोजित संचय : (Accumulation) नियोजित संचय का मतलब है, किसी फर्म की ऐसी इन्वेंट्री जिसका अनुमान लगाया जा सकता है या योजना बनाई जा सकती है।

डिक्यूमुलेशन : (Decumulation) संपत्ति विमुद्रीकरण या डिक्यूमुलेशन का मतलब है अपने पैसे को खर्च करना।

स्टॉक और फ्लो (प्रवाह) : एक स्टॉक को एक विशिष्ट समय पर मापा जाता है, और उस समय (जैसे- 1 जनवरी 2025) पर मौजूद मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अतीत में जमा हो सकता है। एक प्रवाह चर को समय के अंतराल पर मापा जाता है। इसलिए एक प्रवाह को समय की प्रति इकाई (जैसे एक वर्ष) मापा जाएगा।

→ स्टॉक	→ फ्लो
• संपत्ति, ऋण	• आय, व्यय
• इन्वेंट्री	• इन्वेंट्री में परिवर्तन
• पूंजी	• मूल्यह्रास

व्यय विधि :

(Expenditure Method)

$$C + G + I + (X - M)$$

C	G	I	X	M
Consumption उपभोग	Govr. Exp. सरकारी खर्च	Investment निवेश	निर्यात	आयात

PARMAR SSC

C + G + I + Nx

↳ Net export

आय विधि :
(Income method)

- कर्मचारियों का मुआवजा
  - → वेतन, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, पेंशन
  - → किराया, ब्याज, लाभ
- लाभ (किराया और रॉयल्टी, ब्याज)
- मिश्रित आय

राष्ट्रीय आय की गणना:

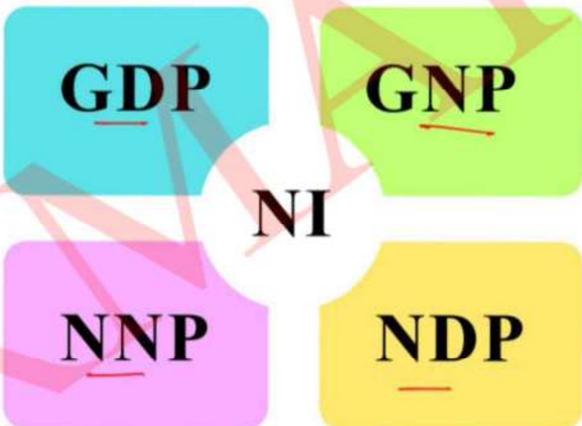

GDP : सकल घरेलू उत्पाद

"किसी भी देश की सीमाओ के भीतर एक समय अवधि मे (आमतौर पर 1 वर्ष) उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओ और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।"

वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल- 31 मार्च

PARMAR SSC

GNP : सकल राष्ट्रीय उत्पाद

" देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किये गये अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। "

GNP = GDP + विदेश से शुद्ध कारक आय

{GDP − FI to abroad + FI from abroad}

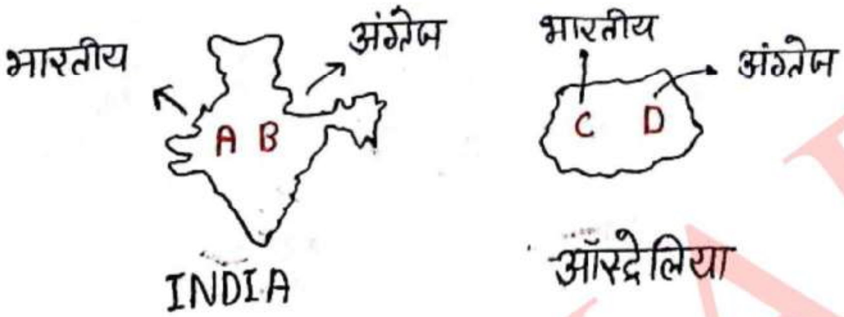

GDP = A + B

GNP = A + C

NDP : शुद्ध घरेलू उत्पाद

किसी परिसंपत्ति का मौद्रिक मूल्य समय के साथ विभिन्न कारकों के कारण घटता है।

परिसंपत्ति- वस्तुएँ और सेवाएँ

- NDP = GDP − मूल्यह्रास

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी)

- NNP = GNP − मूल्यह्रास
- GNP = GDP + NFIA

PARMAR SSC

जीडीपी का विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री 'साइमन कुजनेट्स' ने 1934 में किया था।

बाजार मूल्य

बाजार मूल्य बेचे जा रहे उत्पाद का अंतिम मूल्य है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं।

कारक लागत

कारक लागत उत्पादन के कारकों की लागत या इनपुट का कुल मूल्य है, जहां अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं।

प्रमुख सूत्र:

GDP_{FC} = GDP_{mp} - सकल अप्रत्यक्ष कर

GDP_{FC} = GDP_{mp} - (Indirect Tax / अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)

GDP_{FC} = GDP_{mp} - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

GDP - मूल्यह्रास = ~~सकल DP~~ Net DP

GDP - NFIA = Gross NP

नोट = घरेलू आय GDP के अंतर्गत नहीं आती।

वास्तविक जीडीपी & नाममात्र जीडीपी:

↓

- आधार वर्ष को आधार प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
- स्थिर कीमतों पर गणना
- यह मुद्रास्फीति समायोजित है।

नाममात्र जीडीपी

- मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक GDP से अधिक
- मौजूदा कीमतों पर गणना
- मुद्रास्फीति समायोजित नहीं।

इरविन फिशर उल्लेख इस प्रकार किया :

मौद्रिक भ्रम की अवधारणा

PARMAR SSC

Parle-G → ₹ 100 [10 X 10]

नाममात्र GDP } X2 ← वास्तविक GDP

Parle-G → ₹ 200 [20 X 10] {10 X 10} = 100

↓

मुद्रास्फीति

गणना करने के लिए GDP डिफ्लेटर : → मूल्य सूचकांक

अपस्फीतिकारक: $\frac{\text{नाममात्र GDP}}{\text{वास्तविक GDP}} \times 100$

	2012	2023
बिस्कुट	1000X5 = 5000	900X5 = 4500

आधार वर्ष ↓ 'आधार प्रभाव' Base effect

वास्तविक GDP ↓ नियत मूल्य

नॉमिनल GDP ↓ वर्तमान मूल्य

GDP की गणना : CSO (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय) → MoSPI

आधार वर्ष : 2011-12

● **प्रति व्यक्ति आय :** $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$

PARMAR SSC

क्रय शक्ति समता : यह एक आर्थिक सिद्दांत हैं, यह मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को बताता हैं।

↳ सामान की एक सामान्य टोकरी

किन्ही दो देशो के बीच वस्तु या सेवा की कीमत मे मौजूद अंतर से लिया जाता हैं।

- भारत की GDP दुनिया में 5 वें स्थान पर : (2024 तक)

  - USA
  - चीन
  - जर्मनी
  - जापान
  - भारत

- क्रयशक्ति समता (PPP) में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा

  $1\$ = 87₹$

  ↳ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति

- **व्यक्तिगत / निजी आय :** (Personal Income) किसी व्यक्ति की मजदूरी, निवेश उद्यमों और अन्य उपक्रमों से होने वाली कुल आय (करों के बाद)

निजी आय = NI + आय अर्जित लेकिन प्राप्त नही + आय प्राप्त लेकिन अर्जित नही

PI = NI + Transfer payment − Undistributed corporate profit

PARMAR SSC

◉ **प्रयोज्य व्यक्तिगत आय :** व्यक्तिगत आय - कर

(Personal Disposable Income)

वह धन जो किसी व्यक्ति को करों और अन्य कटौतियों के बाद बचता है।

GDP_{FC} = GDP_{mp} - सकल / Net अप्रत्यक्ष कर

GDP_{FC} = GDP_{mc} - अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

GDP_{FC} = GDP_{mc} - कर + सब्सिडी

- हरित जीडीपी = जीडीपी - पर्यावरणीय क्षति
- संभावित GDP − वास्तविक GDP = मंदी का अंतर

PARMAR SSC

" मुद्रा स्फीति "

" समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतो मे होने वाली एक सामान्य बढ़ोत्तरी "

क्रयशक्ति / purchasing power → कम / घटती

इरविन फिशर : मौद्रिक भ्रम / Money illusion [mV = PT]

◉ मुद्रास्फीति मे किसे लाभ होगा -

ऋणदाता ——→ उधार लेने वाला / Borrower

10,000

↑ फायदे मे रहेगा

मुद्रास्फीति के दौरान ऋणी / उधारकर्ता को ऋणदाता की तुलना में अधिक लाभ होता है।

GDP अपस्फीतिकारक = $\frac{\text{नाममात्र GDP}}{\text{वास्तविक GDP}} \times 100$

धन का परिमाण सिद्धांत :

परिसंचरण का वेग

तैयार माल और सेवाओं की खरीद में एक डॉलर, यूरो आदि कितनी बार खर्च किया जाता है।

सभी लेनदेन

अर्थव्यवस्था के भीतर बेचे गए सभी सामान और सेवाएँ

$$M \times V = P \times T$$

मुद्रा आपूर्ति

अर्थव्यवस्था मे सारा धन

मुद्रा स्तर

अर्थव्यवस्था में सभी सेवाओं का मूल्य स्तर

PARMAR SSC

मुद्रास्फीति के प्रकार :

1. Creeping मुद्रास्फीति → 3-4%
2. Walking मुद्रास्फीति → 4-10%
3. Running मुद्रास्फीति → 10-20%
4. Galloping मुद्रास्फीति → 20-100%
5. Hyper मुद्रास्फीति → 100%

मुद्रास्फीति के कारण :

Demand pull
मांगजनित

- मांग पक्ष मुद्रास्फीति
- बहुत सारे डॉलर, बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहे हैं।

Cost push
लागतजनित

- आपूर्ती पक्ष मुद्रास्फीति
- उत्पादन और इनपुट लागत के किसी भी कारक की लागत में वृद्धि।

मुद्रास्फीति का मापन :

1. WPI

→ Wholesale price Index
थोकमूल्य सूचकांक

- यह थोक व्यवसायी द्वारा अन्य व्यवसायी को बेची जाने वाली वस्तुओ की कीमतो मे बदलाव को मापता हैं।

  विनिर्मित वस्तुओ को अधिक weightage दिया जाता।

2. CPI

→ Consumer price Index
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- खाद्य पदार्थों को अधिक weightage
- आधार वर्ष - 2011-12

  जारी - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
  MoSPI के अंतर्गत

PARMAR SSC

◉ आधार वर्ष - 2011-12

◉ WPI 1st time - 1942

जारी - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT)
↓
Department for promotion of Industry & Internal Trade

" मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI, CPI का उपयोग करती है।" ↳ CPI(C)

↓

लेबर ब्यूरो BY: 1986-87
- CPI - Industrial workers
- CPI - Agricultural workers
- CPI - Rural workers

NSO (MoSPI) BY: 2012
- CPI
  - urban
  - Rural
  - Combined

निर्मित वस्तुयें (64.2%) ⟶ खाद्य & पेय

प्राथमिक वस्तुयें (22.6%) ⟶ घर (10%)

ईंधन ईंधन और शक्ति (13.5%) ⟶ ईंधन, शक्ति (6.8%)

IIP: Index of Industrial Production

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष → 2011-12

प्रकाशित → NSO (MoSPI)

- यह व्यक्तिगत उत्पादन को ट्रेक करता है।
- WPI & CPI मूल्य परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन IIP मात्रा को मापने पर केंद्रित होता है।

8 प्रमुख उद्योगों का 40% योगदान:

1. रिफाइनरी उत्पाद
2. बिजली

PARMAR SSC

3. स्टील
4. कच्चा तेल
5. प्राकृतिक गैस
6. सीमेंट
7. उर्वरक
8. कोयला

अवस्फीति : Disinflation → महंगाई की दर घट रही है। 10% → 8% → 7% → 5%

अपस्फीति : Deflation → मुद्रास्फीति का विपरीत
→ कीमत के सामान्य स्तर मे गिरावट

क्रय शक्ति मे

फिलिप वक्र : मुद्रास्फीति और बेरोजगारी मे स्थिर और विपरीत संबंध है।

स्फीतिजनित मंदी / Stagflation: मुद्रास्फीति ↑ बेरोजगारी ↑

फिलिप वक्र ✗

Great Depression — 1929 - 1939

Great Recession — 2007 - 2009

PARMAR SSC

"बेरोजगारी"

यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है।

- NSSO बेरोजगारी मापने के लिए 3 तरीकों का उपयोग करता है। {
  - सामान्य स्थिति दर
  - साप्ताहिक स्थिति दर
  - दैनिक स्थिति दर

बेरोजगारी के प्रकार:

1. **संरचनात्मक बेरोजगारी** → कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं का बेमेल (शहरी क्षेत्र मे)

उदाहरण: प्रौद्योगिकी उन्नति, जैसे मशीनरी द्वारा किसान श्रम का स्थान लेना।

शिक्षित बेरोजगारी: डिग्री → बेरोजगार (शहरी क्षेत्र मे)

2. **घर्षणात्मक बेरोजगारी** → नौकरियों के बीच अस्थायी बेरोजगारी (नये जॉब की तलाश) (शहरी क्षेत्र मे)

उदाहरण: एक कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर बेहतर नौकरी में चला जाता है।

3. **प्रच्छन्न बेरोजगारी** → आवश्यकता से अधिक लोगो को रोजगार दिया जाता (कृषि क्षेत्र में) (ग्रामीण क्षेत्रमे)

छिपी हुई बेरोजगारी जब कुछ लोग कार्यरत दिखते हैं लेकिन होते नही हैं, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।
जैसे- कृषि क्षेत्र

PARMAR SSC

4. **चक्रीय बेरोजगारी →**

अर्थव्यवस्था मे मंदी (उतार - चढाव)

जब अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती है, तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जैसा कि शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है।

उदाहरण - महान मंदी

5. **मौसमी बेरोजगारी →** मांग मे मौसमी बदलाव के परिणामस्वरूप (ग्रामीण)

शास्त्रीय बेरोजगारी : इसे वास्तविक वेतन बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब किसी नौकरी के लिए वास्तविक वेतन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण नौकरी के अवसरों की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या अधिक हो जाती है।

प्राकृतिक बेरोजगारी: यह बेरोजगारी का वह न्यूनतम स्तर है जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना बनाए रख सकती है।

सीमांत Vs मुख्य श्रमिक

सीमांत	मुख्य श्रमिक
वे व्यक्ति जो पिछले 365 दिनों में 183 दिनों से कम समय के लिए कार्यरत रहे।	वे व्यक्ति जो पिछले 365 दिनों में कम से कम 183 दिन (छह महीने से अधिक) कार्यरत रहे।
अस्थायी / मौसमी	स्थायी / नियमित

PARMAR SSC

संगठित श्रमिक Vs असंगठित श्रमिक

संगठित श्रमिक	असंगठित श्रमिक
वे श्रमिक जो पंजीकृत कंपनी, उद्योग या सरकारी संस्थान के अंतर्गत आते हैं।	वे श्रमिक जो छोटे उद्योगों, निजी व्यवसायों या अस्थायी कार्यों में लगे होते हैं और जिनका कोई निश्चित रोजगार नहीं होता।
अधिक स्थिर और सुरक्षित	अस्थायी और अनिश्चित

→ 1973 की भगवती समिति ने बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट पेश की। इस समिति को आधिकारिक तौर पर रोजगार और आय वितरण पर टास्क फोर्स नाम दिया गया।

NREGA (नरेगा) → 2005
लागू → 2006

↓

MGNREGA (मनरेगा) → 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है।
(अकुशल श्रमिक)

→ हाल ही के अध्ययनों के अनुसार, भारत में अधिकांश बेरोजगार लोग माध्यमिक शिक्षा और उससे ऊपर के स्तर पर हैं।

PARMAR SSC

PARMAR SSC

frequent अक्सर

ब्याज, उधार

↓

Revenue/ राजस्व

कभी-कभी

लोन, Asset sale

↓

Capital / पूंजी

Receipt - इनकम / प्राप्तियाँ

Expenditure - खर्चा

बजट : किसी निर्दिष्ट समयावधि में राजस्व और व्यय का अनुमान

वार्षिक वित्तीय विवरण - अनुच्छेद 112 → राष्ट्रपति

- बजट तैयार करता - आर्थिक मामलो का विभाग
- बजट प्रस्तुत करता - वित्त मंत्री

PARMAR SSC

- पहला बजट - R. K. षणमुखम चेट्टी
- दूसरा बजट - जॉन मथाई
- सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुतकर्ता - मोरारजी देसाई (10 बार) → लगातार 6 बार
  - पी. चिदंबरम (9 बार)
  - प्रणब मुखर्जी (8 बार)

निर्मला सीतारमन : 8 बार

↳ लगातार बजट को अधिकतम संख्या में प्रस्तुत किया।

लिंग-संवेदनशील बजट - 2005-06

→ 2016 - विवेक देवरॉय समिति - जनरल बजट + रेलवे बजट

→ 1921 - एकवर्थ समिति - सामान्य बजट / रेलवे बजट

बजट के मुख्य कार्य

(3)

आवंटन कार्य
- सार्वजनिक वस्तुएँ & सेवाओं का प्रावधान

पुनर्वितरण कार्य
- कराधान नीति
- सामाजिक कल्याण योजनाएं
- सब्सिडी & अनुदान
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- रोजगार सृजन
- सामाजिक सुरक्षा

स्थिरीकरण कार्य
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
- बेरोजगारी कम करना
- आर्थिक मंदी से बचाव
- वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना
- विनिमय दर को स्थिर रखना।

PARMAR SSC

बजट (Government Budget)

- राजस्व बजट
  - राजस्व प्राप्तियाँ
    - कर राजस्व
    - गैर कर राजस्व
  - राजस्व व्यय
    - योजना राजस्व व्यय
    - गैर योजना राजस्व व्यय
- पूंजी बजट
  - पूंजी प्राप्तियां
  - पूंजी व्यय
    - योजना पूंजीगत व्यय
    - गैर योजना पूंजीगत व्यय

संपत्ति : किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति (ऐसी वस्तु जिसका आर्थिक मूल्य हो)
जैसे - सोना , संपत्ति (Property)

देयता : ऐसा कुछ जिसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो (ऋण/ दायित्व)
जैसे - ऋण का भुगतान

राजस्व

बारंबार लेन-देन (Frequent Transaction)

- **राजस्व प्राप्तियाँ** — सरकार को इन्हें वापस करने की जरूरत नहीं होती।
  न तो संपत्ति में कमी होगी न ही देयता में वृद्धि होगी।
  - **कर राजस्व** — उदा० - संपत्ति कर
  - **गैर-कर राजस्व** — उदा० - चालान, रेल टिकट, PSU से कमाई
- **राजस्व व्यय**
  न तो परिसंपत्ति में वृद्धि होगी और न ही देयता में कमी होगी।
  - **योजनागत राजस्व व्यय** (अनुदान / वित्तीय परिसंपत्ति)
  - **गैर- योजनागत राजस्व व्यय** (वेतन, पेंशन)
  - वेतन, पेंशन
  - सब्सिडी / अनुदान
  - ब्याज भुगतान
  - बुनियादी ढांचे का रखरखाव

PARMAR SSC

पूंजी

कम बार (Less frequent)

पूंजीगत प्राप्ति

परिसंपत्ति ↓
देयता ↑

- लोन / ऋण
- विनिवेश

पूंजीगत व्यय

परिसंपत्ति ↑
देयता ↓

- लोन देना
- ऋण का भुगतान
- विकासात्मक व्यय
  ↳ बुनियादी ढांचे का विकास
  (सड़क, अस्पताल, स्कूल का निर्माण)

राजस्व व्यय →
- → अवसर
- → न तो Asset बढ़ रहा है न ही Liability घट रही है।

पूंजीगत व्यय →
- → कभी-कभी
- → Asset ↑
  Liability ↓

- वेतन / Salary - राजस्व व्यय
- लोन / Loan - पूंजीगत व्यय
- ब्याज - राजस्व
- अनुदान / grant - राजस्व

लोन / ऋण →
- → मूलधन - पूंजीगत
- → ब्याज - राजस्व

राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
वेतन, पेंशन	निर्माण (किसी भी बुनियादी ढांचे का)
सब्सिडी / अनुदान	जमीन / मशीनरी की खरीद
ब्याज, रखरखाव	निवेश, लोन
	ऋणों का पुनर्भुगतान

PARMAR SSC

कराधान / TAXATION

प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1. सीधे सरकार को भुगतान	1. सरकार को सीधे भुगतान नही किया जाता
2. इन करो को किसी अन्य इकाई मे स्थानांतरित नही किया जा सकता है।	2. यह किसी अन्य इकाई मे स्थानांतरित किया जा सकता है।
3. प्रगतिशील कर	3. प्रतिगामी कर / Regressive tax
उदा०: आय कर, Weath Tax, उपहार कर, Capital gains कर	उदा: GST (101 वां संविधान संशोधन)

GST (101 वां संविधान संशोधन)
- 1 जुलाई 2017
- असम - पहला राज्य
- GST Council - अनु० 279 A
  - अध्यक्ष - वित्त मंत्री
  - 33 सदस्य
    - 2 केन्द्र से
    - 31 (राज्यो से) + केन्द्र शासित प्रदेशो से

- उत्पाद शुल्क: पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन

पेपर कर : संपत्ति कर, उपहार कर, एस्टेट ड्यूटी (अप्रचलित)

→ राजस्व संग्रह बहुत कम होता है।

प्रत्यक्ष कर में, सीमांत कर दर > औसत कर दर

अंतरिम बजट : चुनावी वर्ष पर प्रस्तुत

PARMAR SSC

DEFICITS/घाटे :

प्राप्तियाँ/ इनकम > खर्च = सरप्लस बजट

खर्चा > इनकम = बजट घाटा/ डेफिसिट बजट

व्यय = प्राप्ति → संतुलित बजट

घाटा के प्रकार

1. **बजटीय घाटा/** Budgetary deficit
2. **राजस्व घाटा** → राजस्व खर्च - राजस्व प्राप्तियाँ
3. **राजकोषीय घाटा** → कुल खर्च - सरकार की कुल आय
   (राजस्व प्राप्ति + ऋणो की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)
   - TE - [RR + non debt creating CR]
   - TE - [TR - debt creating CR]
4. **प्राथमिक घाटा** → राजकोषिय घाटा - ब्याज/ Interest payment
5. **प्रभावी राजस्व घाटा** → राजस्व घाटा - पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष : 31 मार्च - 1 अप्रैल

→ **सरचार्ज :** कर पे कर

→ **सेस :** एक निश्चित उद्देश्य के लिए , सभी पर लगता

PARMAR SSC

केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा साझा नहीं किया जाता है।

→ **पिग्गोवियन कर:** किसी भी सामान के लेन-देन पर लगाया जाने वाला कर है, जो नकारात्मक बाहरी कारक का सृजन करता है।

SEBI/सेबी: 12 अप्रैल 1988, माधवी पुरी बुच
HQ - मुम्बई

FRBM Act → 2003

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM)

3 मुख्य नीतिगत बयान:

1. मध्यमकालिक राजकोषीय नीति वक्तव्य -
   ↳ यह वक्तव्य 3 साल की अवधि के लिए सरकार की राजकोषीय नीति नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। इसका उद्देश्य सरकार की वित्तीय स्थिति, खर्च और राजस्व प्रबंधन पर लंबी अवधि में निगरानी रखना है।

2. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य - यह सरकार के वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

3. माइक्रोइकोनॉमिक्स ढांचा वक्तव्य - GDP वृद्धि दर

PARMAR SSC

MONEY $

BANKING

बैंकों द्वारा निष्पादित वित्तीय गतिविधियां - बैंकिंग

RBI - भारतीय रिजर्व बैंक

हिल्टन यंग कमीशन - 1926 → बीआर अम्बेडकर से भी ली गई सिफारिशें

RBI अधिनियम - 1934

↓

1 अप्रैल 1935 स्थापना

HQ - कलकत्ता
वर्तमान - मुम्बई
) 1937

कार्य: 1. बैंकिंग सिस्टम की देख-रेख

बैंक → लाइसेंस देना → CRR/SLR, ब्याज दर

विनियमन / Regulate → बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

2. करेंसी प्रिंटिंग

(1 ₹ को छोड़कर → वित्तमंत्रालय)

→ कानूनी निविदा / Legal tender → FIAT Money

प्लास्टिक मुद्रा - क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि।

हॉट मनी / मुद्रा - परिसंपत्तियां जैसे - स्टॉक, जमा, बांड आदि।

आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था।

प्रथम RBI गवर्नर : ओसबोर्न स्मिथ

प्रथम भारतीय RBI गवर्नर - सीडी देशमुख

PARMAR SSC

मुद्रा मुद्रण	सिक्के- GOI- ₹1 नोट
नासिक	मुंबई
देवास	हैदराबाद
मैसूर	कलकत्ता
सालबोनी	नोएडा

3. मौद्रिक नीति

4. आखिरी कर्जदाता / Lender of last Resort

"बैंको का बैंक कहा जाता।"

स्वच्छ नोट नीति : 1999

- रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति का उद्देश्य नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है, जबकि गंदे नोटों को प्रचलन से बाहर करना है।
- फिएट मनी एक प्रकार की मुद्रा है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है और यह सोने या चांदी जैसे किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होती है।

RBI ACT 1934

- अनुसूचित बैंक ← दूसरी अनुसूची के तहत RBI अधिनियम 1934
  - वाणिज्य बैंक (Commercial)
  - सहकारी बैंक (Cooperative)
- गैर- अनुसूचित बैंक

PARMAR SSC

वाणिज्य बैंक — Commercial — Profit

सहकारी बैंक — Cooperative — Non-profit

वाणिज्य बैंक:
- सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक
  - 11 राष्ट्रीयकृत बैंक + SBI बैंक
  - 12 बैंक
- निजी / Private Sector बैंक Bank
  - भारतीय: HDFC, ICICI, KOTAK
  - विदेशी: CITI बैंक, HSBC

वित्तीय समावेशन के लिए, बैंको का राष्ट्रीयकरण-
1969 → 14 बैंक
1980 → 6 बैंक

भारत मे बैंकिंग प्रणाली का इतिहास :

◉ पहली बैंक - 1770 बैंक ऑफ हिन्दुस्तान

1806 - कलकत्ता बैंक
1840 - बॉम्बे
1843 - मद्रास

} इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया 1921 → (1955) SBI

◉ पहला भारतीय स्वामित्व बैंक - इलाहाबाद बैंक (1865)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) - 1975

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय गतिविधियों को बढ़ाने के लिए
RBI अधिनियम 1976

1st RRB - प्रथमा ग्रामीण बैंक [2 अक्टूबर 1975]
↳ UP के मुरादाबाद मे

PARMAR SSC

ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना की गई थी।

RRB

- विनियमित (RBI द्वारा)
- पर्यवेक्षण (नाबार्ड द्वारा)

RRB
→ 50% हिस्सेदारी - केंद्र
→ 15% " राज्य
→ 35% " स्पोंसर बैंक

अन्य वित्तीय संस्थान:

नाबार्ड / NABARD:
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
- नाबार्ड अधिनियम 1981
- 12 अप्रैल 1982 को स्थापित, HQ - मुम्बई

"बी. शिवरमन समिति पर 1979 मे गठन"

कार्य: 1. ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित उपलब्ध कराना।

2. सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का पर्यवेक्षण / Supervise करता है।

→ PMAY, KCC, RuPay Kisan Card

सिडबी: 2 अप्रैल 1990
मुख्यालय - लखनऊ
↳ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

PARMAR SSC

2015 में नाबार्ड में 'ई-शक्ती' और 'एलईडीपी' (आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम) पहल शुरू की थी।

राष्ट्रीय आवास बैंक : 1988

सेबी : सेबी अधिनियम → 1992

12 अप्रैल 1988

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

HQ - मुम्बई

कार्य : निवेशकों के interests की रक्षा

चेयरपर्सन : माधबी पुरी बुच (पहली महिला अध्यक्ष)

IRDAI : IRDAI अधिनियम 1999 , अप्रैल 2000

पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

NAFED : भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड- 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित।

IDBI : इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा RBI की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। बाद में LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने बैंक में 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली।

PARMAR SSC

सूक्ष्म वित्त संस्थायें / Micro finance Institutions :

भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए RBI ने MFI को विनियमित किया।

" यह कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती। "

→ लोन, इंश्योरेंस, बचत

सूक्ष्म वित्त लोन : पात्र व्यक्ति → जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख हो।

→ Collateral free loan
गिरवी मुक्त लोन

सूक्ष्म वित्त संस्था के पिता - मो. युनुस (बांग्लादेश)
↳ ग्रामीण मॉडल बैंक - 1970
नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता
(बांग्लादेश ग्रामीण बैंक)

भारत में प्रथम माइक्रो फाइनेंस संस्थान : **SEWA बैंक** (1974)
↳ स्वरोजगार महिला एसोसिएशन
(अहमदाबाद में स्थापित)

बिजनेस मॉडल :

◎ स्वयं सहायता समूह - 10-20 लोगों का समूह , BPL का समूह
↳ Blow poverty line

PARMAR SSC

◉ संयुक्त देयता समूह 4-10 लोगो का

↙ ↘

न्यूनतम अधिकतम

→ उद्देश्य- लाभ

MUDRA : Micro units Development & Refinance Agency

1. शिशु लोन : 50 हजार तक ऋण
2. किशोर ऋण : 5 लाख तक
3. तरुण ऋण : 5-10 लाख तक → 2024 मे बढकर 20 लाख

'2015 मे लांच'

→ गिरवी मुक्त ऋण

नाबार्ड ने 1992 में SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरु किया।
नाबार्ड ने MFI बैंक लिंकेज मॉडल भी शुरु किया।

NBFC : बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा & महिंद्रा

◉ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत
◉ ऋण और एडवांस देने का काम
◉ यह मांग जमा स्वीकार नही कर सकता।
(Demand Deposits)
◉ जमा/ deposits की गारंटी नही।
◉ यह RBI के द्वारा Regulate होती।
◉ CRR, SLR को maintain करने की आवश्यकता नही।

PARMAR SSC

NBFC-MFI :

माइक्रोफाइनेंस लोन की न्यूनतम आवश्यकता - कुल संपत्ति (assets) का 85 %.

'मालेगाम समिति की सिफारिश पर गठन'
↓
2010

- सूक्ष्म ऋण / सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।
- NBFC-MFI के अलावा अन्य माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर अधिकतम सीमा कुल परिसंपत्ति का 25 %.
- NBFC-MFI लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उनके पास माइक्रोफाइनेंस में कम से कम 75 % संपत्ति होनी चाहिए।

ऋण-चुकौती मासिक दायित्व की सीमा - 50 %

EXIM Bank :

आयात- निर्यात बैंक - अधिनियम 1981
↓
1982

HQ - मुम्बई

SIDBI :

2 अप्रैल 1990

HQ - लखनऊ

Small Industries development Bank of India

वित्तमंत्रालय के अन्तर्गत

IDBI :

Industrial development Bank of India

अधिनियम - 1964

BSE : Bombay Stock exchange
1875

NSE : National stock exchange
1992

PARMAR SSC

मौद्रिक नीति :

NDTL : Net demand & Time liability
मांग और समय देनदारियां

Demand Liability
- → Saving बचत खाता
- → Current चालू खाता

Time Liability
- → Fixed deposite सावधि जमा खाता
- → Recurring dep. आवर्ती जमा खाता

RBI आपके NDTL का एक हिस्सा आरक्षित के रूप में रखता है।

बेलेंस सीट

- देयता (Liability)
  - ↓ जमा (Deposits)
    - मांग जमा Demand deposits
      - ↓
      - बचत खाता
      - चालू खाता
        - ↓ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए
    - सावधि जमा Time / Term Deposits
      - ↳ • सावधि जमा (Fixed deposite) (एक निश्चित समय पर परिपक्व होती है)
      - • आवर्ती जमा (जैसे - म्यूचुअल फंड में SIP)
- परिसंपत्ति (Asset)
  - ↓ ऋण (Loan)

PARMAR SSC

Different Assets and Liabilities of a Commercial Bank

BALANCE SHEET			
LIABILITIES	**AMT**	**ASSETS**	**AMT**
Share Capital		Vault Cash	
Loan taken from Central Bank if any		Deposits with Central Bank	
Demand Deposits		Loans	
Term Deposits		Investment in Government Securities	
Total		**Total**	

Share Capital ← Initial Money Invested

Loan taken from Central Bank if any ← Sometimes bank borrows money from RBI

Demand Deposits ← Saving Account, Current Account

Term Deposits ← Fixed Deposits/ Recurring Deposits

Vault Cash → Cash kept in Bank for Withdrawal by customers

Deposits with Central Bank → Amount deposited by Bank with RBI

Loans → Loan Given to Public

Investment in Government Securities → Amt invested in Government Bonks

CRR: Cash Reserve Ratio

नकद आरक्षित अनुपात

No profit
IR

↳ RBI के पास रखा जाता है जो एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि के प्रतिशत को संदर्भित करता है।

SLR: Statutory Liquid Ratio

वैधानिक तरलता अनुपात

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं बनाए रखा जाता है।

नकद, सोना, G.sec (Government Security)

IR मिलता है। (Interest Rate)

Liquidity: {तरलता} बैंकिंग प्रणाली मे अधिक तरलता आसानी से उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है। जिससे बैंक अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करता है।

PARMAR SSC

1. Cash → अधिक तरल / Most Liquid
2. Gold Chain
3. Property → कम तरल / Least Liquid

मुद्रास्फीति / अपस्फीति → मूल्यों के स्तर में वृद्धि { Demand Pull, Cost Push }

मुद्रास्फीति / अपस्फीति → RBI → मुद्रा आपूर्ति को नियन्त्रित

↓

मौद्रिक नीति उपकरण / घटक

RBI ↓ मौद्रिक नीति ↓ (उपकरणों के प्रयोग से) मौद्रिक नीति उपकरण

मुद्रा गुणक : बैंको द्वारा आरक्षित निधि के प्रत्येक डॉलर के लिए बनाई गई नई मुद्रा की अधिकतम राशि।

$$mm \propto \frac{1}{CRR}$$

मौद्रिक नीति समिति: उर्जित पटेल की सिफारिश पर

6 सदस्य
- 3 RBI
  - गवर्नर
  - डिप्टी गवर्नर
  - कार्यकारी अधिकारी
- 3 - सरकार द्वारा

PARMAR SSC

मौद्रिक नीति उपकरण

- मात्रात्मक उपकरण
  - बैंक दर
  - खुला बाजार संचालन
  - सीमांत स्थायी सुविधा
- गुणात्मक उपकरण

दर/ Rates : (मात्रात्मक उपकरण)

1. बैंक दर : 6. 5%

बैंक ⟶ RBI

लोन लेने ⟶ लम्बे समय के लिए

कोई गिरवी नही

RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है
(बिना कोई प्रतिभूति रखे)

2. खुला बाजार संचालन / Open Market Operation :

- मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियन्त्रित करने के लिए, फैडरल रिजर्व सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना।

मुद्रास्फीति → सरकारी प्रतिभूतियो को बेचना

खुला बाजार संचालन

- एकमुश्त खरीद (Outright Purchase)
- पुनर्खरीद समझौता (Repurchase Agreement)
  - → संपार्श्विक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियाँ

PARMAR SSC

→ लघु अवधि

सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद -

G-sec ⇄ नकद

जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री

{ रेपो का मतलब है पुनर्खरीद दायित्व }

पुनर्खरीद समझौता

रेपो दर ← → रिवर्स रेपो दर

रेपो दर:

6.25%

बैंक ⟶ RBI

लोन ⟶ कम समय के लिए, गिरवी युक्त

↳ Overnight loan

रिवर्स रेपो दर:

'RRR'

RBI ⟶ बैंक

रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति पर नियंत्रण।

→ RR & RRR को सामूहिक रूप से तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) कहा जाता है।

3. **सीमांत स्थायी सुविधा :** marginal standing facility :

- आपातकालीन स्थिति मे RBI से उधार लेना
- 6.75%

PARMAR SSC

- रात्रिकालीन ऋण (overnight Loan)
- 2% NDTL एक सीमा

- CRR और SLR को बनाए नहीं रखा जाता।
- जुमाना + ऋण
- SLR कोटा G-Sec को संपाश्विक के रूप में उपयोग कर सकते है।

NBFC, MFI } CRR & SLR को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं।

अल्पकालीन G-Sec
↓
ट्रेजरी बिल
↙ ↓ ↘
91 दिन | 182 दिन | 364 दिन

उपकरण / Tools

CRR, SLR, BR, RR, RRR

Case-1

मुद्रास्फीति के दौरान

- नियामकों मे वृद्दि
- मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए ब्याज दरों मे वृद्दि

CRR, SLR, BR, RRR, RR ↑

संकुचनकारी / Tight / Dear / हॉकिश मौद्रिक नीति

Case-2

अपस्फीति के दौरान

CRR, SLR, BR, RRR, RR ↓

- नियामकों में कमी
- ब्याज दरों में कमी

डोविश / Easy / विस्तारवादी मौद्रिक नीति

PARMAR SSC

उपकरण / घटक

- अनुपात
- दर

अनुपात ↓

↑ CRR - नकद आरक्षित अनुपात
SLR - वैधानिक तरलता अनुपात

↑ → हॉकिश मौद्रिक नीति (Tight/deal) → उच्च ब्याज दरों को बनाये रखना (मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए)

CRR ↓
SLR ↓ डोविश मौद्रिक नीति (Easy) → जब ब्याज दरों मे कटौती की जाती है।

मुद्रा जमा अनुपात = Currency deposit Ratio = $\frac{\text{जनता द्वारा मुद्रा के रूप में रखा गया धन}}{\text{बैंक में जमा के रूप में धन}}$

G-sec.
- बेचना → मुद्रास्फीति
- खरीदना → अपस्फीति

राजकोषीय नीति / Fiscal Policy

भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति या अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कर ↑ सब्सिडी ↓ msp ↑

कर ↑ → ↓ कम प्रयोज्य आय

सब्सिडी ↓, msp ↑ → मुद्रास्फीति

PARMAR SSC

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण:

1. ऋण की राशनिंग
2. उपभोक्ता ऋण का विनियमन
3. सीमांत आवश्यकता मे परिवर्तन
4. नैतिक उत्तेजना

Qualitative monetary policy tools of central bank

This slide shows the four major tools used by central bank of an economy to control credit and inflation. It includes rationing of credit, change in marginal requirements, regulation of consumer credit and moral suasion

Rationing of Credit

- Certain amount is fixed for industrial, household and other purposes
- Credit supply for each commercial bank is fixed
- Add text here

Change in marginal requirements

- Margin is increased for unnecessary sectors
- Margin is decreased for necessary sectors
- Add text here

Regulation of consumer credit

- Instalment amount, down payment, loan duration are all fixed in advance
- Used to control inflation in country
- Add text here
- Add text here

Moral suasion

- Credit limit for each sector is imposed by rules and regulations
- Guidelines and regulations are fixed by central bank for speculative purposes
- Add text here

PARMAR SSC

तरलता : यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और इसे अन्य वस्तुओं के लिए बहुत आसानी से बदला जा सकता है। तरलता वह आसानी है जिसके साथ किसी परिसंपत्ति या सुरक्षा को उसके बाजार मूल्य को प्रभावित किए बिना नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

उदाहरण:
- नकद
- चेक
- सोना
- बॉंड

नकद > सोना > चेक > बॉण्ड
←——————————
तरलता

डिमांड डिपॉजिट (मांग जमा), टर्म डिपॉजिट से अधिक तरल है।

"धन वह है जो धन करता है" यह अर्थशास्त्री प्रोफेसर वॉकर द्वारा धन की परिभाषा है।

धन के कार्य :

- यह विनिमय का एक माध्यम है।
- यह खाते की एक इकाई है।
- यह मूल्य का भंडार है (इसमें कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, सोने जैसी वस्तुओं के विपरीत, आधुनिक कागजी मुद्रा का मूल्य सरकारी समर्थन के कारण है)
- अत्यधिक वहनीय (Portable), टिकाऊ (समय के साथ खराब नहीं होता), विभाज्यता

लोग पैसा क्यों रखते हैं ?

इसमें अवसर लागत शामिल है।

इसके दो कारण हैं-

लेनदेन का उद्देश्य : वस्तुओं और सेवाओं पर सुचारू व्यय की सुविधा के लिए धन रखा जाता है।

सट्टा उद्देश्य: लोग निवेश के अवसरों का लाभ उठाने या संभावित नुकसान से बचने के लिए पैसा रखते हैं।

PARMAR SSC

जॉन मेनार्ड कीन्स के धन मांग के सिद्धांत में एक सट्टा उद्देश्य शामिल है, जो निवेश के अवसरों के लिए धन रखने की इच्छा है।

पैसों की सट्टा मांग ↑ ∝ $\frac{1}{\text{पैसे की दर} \downarrow}$

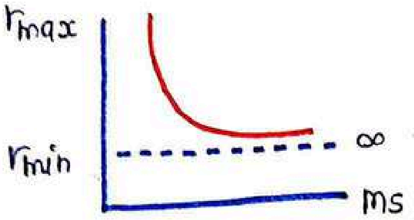

$$m_s = \frac{r_{max} - r}{r - r_{min}}$$

r_{max} - अधिकतम ब्याज दर
r_{min} - न्यूनतम ब्याज दर

अन्य परिभाषा: तरलता जाल वह बिंदु है जहां धन की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता वरीयता वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है।

तरलता जाल: अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जहां लोग ब्याज दरों में किसी भी बदलाव के बावजूद अपना पैसा रखना पसंद करते हैं, जिससे कोई भी मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है।

सट्टा मांग- पूर्णतया लोचदार

↓ कोई खर्च नहीं
↓ ऐसा तब होगा जब दरें बढ़ेंगी

नकद > चेक > बॉण्ड

- नकद — फिएट मुद्रा
- चेक — प्रत्ययी मुद्रा → आपसी समझौते
  Ex- चेक, बिटकॉइन

प्रचलन में मुद्रा:

1. बैंकों के पास मौजूद मुद्रा जिसे बैंक अपने दैनिक कामकाज के लिए रखते हैं।
2. जनता के पास मुद्रा

PARMAR SSC

बैंकों में जमा :

1. **मांग जमा :**
   - बचत खाता
   - चालू खाता
2. **सावधि जमा :** (Term Deposits)
   - फिक्स्ड डिपोजिट (Fixed Deposits)
   - आवर्ति जमा (Recurring Deposits)

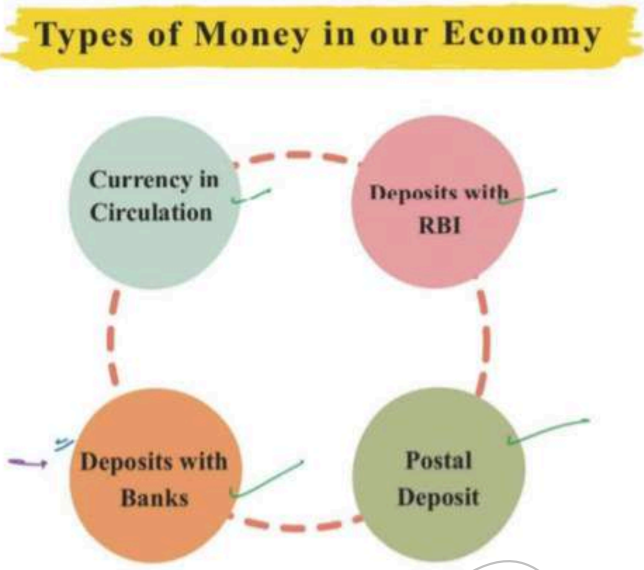

RBI के पास जमा :

1. RBI के पास बैंक जमा (CRR शामिल)
2. RBI के पास अन्य जमाराशियां (सरकारी संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और कुछ निजी संस्थाओं की जमाराशियां)

डाक जमा :

1. मांग जमा } बैंक के समान
2. सावधि जमा }

मौद्रिक समुच्चय / monetary aggregates

मौद्रिक समुच्चय का उपयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए किया जाता है।

RBI → तरलता की जांच
↓
Usable

M0 [आरक्षित धन] →
उच्चशक्ति प्राप्त धन
आधार धन

1. वह मुद्रा जो परिचालित की जा रही है।
2. RBI के पास बैंकरों की जमा
3. RBI के पास अन्य जमाएँ

PARMAR SSC

M_1 : नैरो मनी {Narrow money} →
1. वह मुद्रा जो जनता की है।
2. बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा / मांगजनित
3. RBI के पास अन्य जमा।

M_2 : Narrow मनी → m_1 + डाकघर के साथ बचत जमा

M_3 : } ब्रॉड मनी → m_1 + बैंक के साथ सावधि जमा (Time deposit)

M_4 : → m_3 + डाकघर में पूरा जमा

वास्तविक मुद्रा आपूर्ति और इसे मौद्रिक समुच्चय भी कहा जाता है।

तरलता के आधार पर: $M_1 > M_2 > M_3 > M_4$

मुद्रा गुणक / Money Multiplier:

$$\text{मुद्रा गुणक} = \frac{1}{\text{आरक्षित निधि अनुपात}} = \frac{\text{प्रचलन में मुद्रा}}{\text{रिजर्व मुद्रा}}$$

"प्रत्येक राशि के भंडार के संयोजन में बैंक जो राशि उत्पन्न करता है, उसे धन गुणक कहा जाता है।"

दर / Rate : इंटर-बैंक धन का निगमन
Interbank money transfer
(इसे ऑफर दर भी कहा जाता है)

PARMAR SSC

एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875

LIBOR- London Interbank offer Rate

MIBOR- Mumbai " " "

हटाया गया - 31 दिसंबर 2021

SOFR- Secured overnight financial Rate

मुद्रा बाजार : कम समय के लिए ऋण

कॉल मनी - एक ही दिन मे लौटाना

नोटिस मनी - 2 से 14 दिन मे लौटाना

पूंजी बाजार : लम्बे समय के लिए लोन

ट्रेजरी बिल : Maturity Period - 1 साल से कम

91 दिन | 182 दिन | 364 दिन

- हमेशा छूट की दर / discount rate पर listed होता
- कोई ब्याज दर नही होती।
- RBI द्वारा जारी किये जाते हैं।

बैड बैंक / Bad Banks : NPA की Recovery

बैड बैंक का उद्देश्य बैंको की उनकी बैलेंसशीट से बैड लोन को समाप्त कर बोझ को कम करना है और उन्हे बिना किसी बाधा के ग्राहको को फिर से उधार देना है।

PARMAR SSC

2 बैडबैंक
- National Asset Reconstruction company Ltd. (NARCL)
- India debt Resolution company Ltd. (IDRCL)

परिसंपत्ति (Assets):

परिसंपत्तियां किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व वाले संसाधन हैं जिनका आर्थिक मूल्य (आरक्षित ऋण) होता है।

संपत्ति के प्रकार:

1. **नियमित परिसंपत्तियाँ:** वे जो अधिक दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। (नियमित ब्याज दर + मूलधन)

2. **तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ :** वे ऋण जो निष्पादित नहीं कर रहे हैं, या निष्पादित न करने का खतरा है।
(अतिदेय विलंब 90 दिनों से कम है)

3. **NPA (गैर- निष्पादित परिसंपत्तियाँ):** अतिदेय विलम्ब 90 दिनों से अधिक

वर्गीकृत :- सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट

- सबस्टैंडर्ड एसेट ↓ 3-12 महिने से अधिक समय से बकाया।
- डाउटफुल एसेट ↓ 12 महिने से अधिक समय से बकाया।

नॉन परफॉर्मिंग एसेट: NPA - गैर- निष्पादित संपत्ति

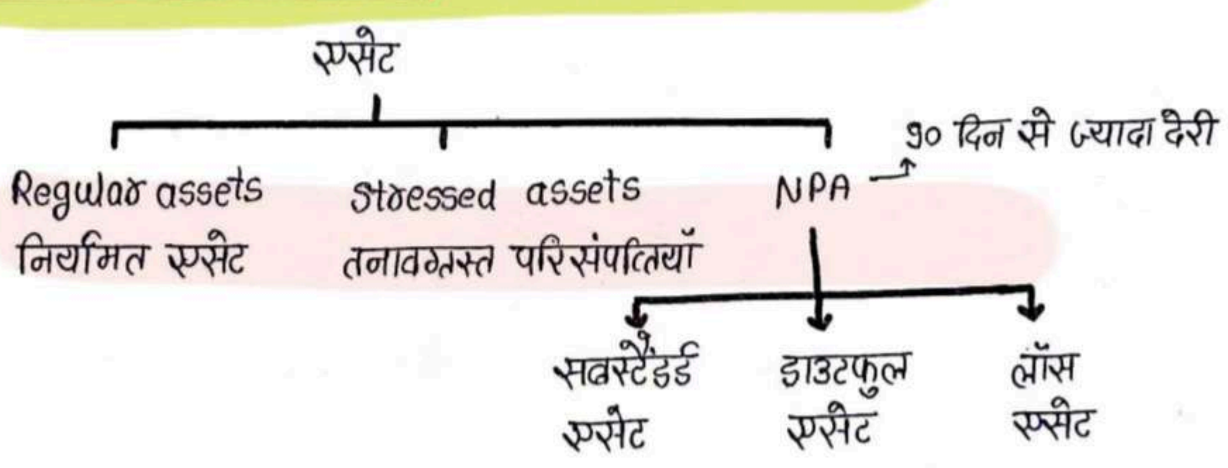

PARMAR SSC

SARFAECI : सरफेसी अधिनियम 2002

ऐसा कानून जो भारतीय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना क्रेडिट डिफॉल्टरों की संपत्ति / प्रॉपर्टीज को बेचने या नीलाम करने की अनुमति देता है।

Securitisation & Reconstruction of Financial assets & enforcement of Security interest act 2002.

विलफुल डिफॉल्टर : किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से लिये गए कर्ज की राशि (Willful defaulter) को जानबूझकर बैंक को वापिस न करना।

Insolvancy & Bankruptcy code

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) - 2016

इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों & व्यक्तियों के दिवालिया होने और दिवालियापन को प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से निपटाना है।

बेसल मानदंड / Basel Norms :

↓

स्वीट्जरलैण्ड

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का HQ - BASEL 1930

बेसल समिति - 1974, G10

1. बेसल 1 : 1988

क्रेडिट जोखिम

- भारत ने वर्ष 1999 में बेसल 1 को अपनाया।

PARMAR SSC

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता जोखिम - भारित परिसंपत्तियों के 8%. के रूप मे निर्धारित (Risk - weighted assets)(RWA)

↳ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital adequacy Ratio) (CAR)

जैसे:

		जोखिम
➔ वेतनभोगी कर्मचारी	: 100%.	0
➔ रतन टाटा	: 90%.	10%.
➔ अशनीर ग्रोवर	: 50%.	50 %.
➔ विजय माल्या	: 10 %.	90 %.

CAR: पूंजी पर्याप्तता अनुपात
CRAR: पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात

- बेसल स्विटजरलैंड में एक स्थान है।
- बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेंटलमेंट्स (BIS) का मुख्यालय - बेसल, स्विटजरलैण्ड (1930 में बेसल समिति द्वारा, 1974 में G10 द्वारा गठित)

MBFC- MFI ⟶ CAR ➔ 15%. of RWA

2. **बेसल 2** : 2004
3. **बेसल 3** : 2010 ⟶ 10.5%

Tier 1 } Capital ⟶ बेसल मानदंड
Tier 2 }

- यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को c से दर्शाया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को किस रुप मे व्यक्त किया जा सकता है- $\frac{1}{1-c}$

PARMAR SSC

गरीबी / Poverty

1. **सापेक्ष गरीबी** - जीवन स्तर के न्यूनतम मानक का अभाव
2. **निरपेक्ष गरीबी** - व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र & आश्रय जैसी जीवन की आवश्यकताओं का अभाव।
3. **व्यक्तिपरक गरीबी:** किसी व्यक्ति की अपनी वित्तीय स्थिति और भौतिक भलाई के बारे में धारणा।

गरीबी का आकलन:

1. **स्वतंत्रता से पूर्व:** दादा भाई नौरोजी - Poverty & unbritish rule in India

↓ सबसे पहले गरीबी का आकलन किया

↓ भारत से धन के पलायन की बात की गई।

भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति।
उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत में गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 16 से 35 ₹ के बीच होगी।

राष्ट्रीय योजना समिति / National Planning committee : 1938

→ S.C. बोस

प्रथम अध्यक्ष - जवाहर लाल नेहरू

बॉम्बे प्लान : 1944 - उद्योगपतियों का एक समूह

↳ इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया।

₹ 75 प्रति व्यक्ति आय / वर्ष

PARMAR SSC

→ प्रोफेसर वी. के. आर. वी. राव ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्दति का इस्तेमाल किया था।

→ राष्ट्रीय योजना समिति ने अनुमान लगाया कि भारत में गरीबी रेखा 15 से 20 ₹ प्रति व्यक्ति प्रति माह के बीच है।

आजादी के बाद:

1. **दांडेकर एवं रथ समिति:** 1971, 'गरीबी का प्रारंभिक व्यवस्थित मूल्यांकन'

NSSO के डाटा के आधार पर 'खर्च के आधार पर गरीबी रेखा'

NSSO - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

2. **अलघ समिति:** 1979 'पोषण के आधार पर गरीबी रेखा'

योजना समिति के अनुसार

- ग्रामीण - 2400 कैलोरी → 49.09 ₹/महिना
- शहरी - 2100 कैलोरी → 56.64 ₹/महीना

} उपभोग/व्यय

3. **लकड़ावाला समिति:** 1993 'CPI-IW & CPI-AL के आधार पर गरीबी रेखा

CPI-IW ↓ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिकों

CPI-AL → CPI - कृषि मजदूरो

"राज्यों के अनुसार गरीबी रेखा | Statewise PL"

4. **सुरेश तेंदुलकर समिति:** 2009 स्वास्थ्य & शिक्षा को भी मूलभूत आवश्यकताओ मे लेना।

PARMAR SSC

- क्रय शक्ति समता पर आधारित गरीबी रेखा : यदि कोई व्यक्ति 33₹/दिन से अधिक व्यय कर रहा है (गरीब नही),
33₹/दिन से अधिक नही (गरीब)

गरीबी मानक [ग्रामीण - 816 ₹ प्रति महिना
शहरी - 1000 ₹ / महिना

गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियो का प्रतिशत - 21.9% (2011-12) { शहरी - 13.7% ; ग्रामीण - 25.7%

→ गरीबी अनुपात : 29.5% { शहरी - 26.4% ; ग्रामीण - 30.9%

तेंदुलकर समिति (2005 में गठित और 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई)

समान संदर्भ अवधि
↓ प्रतिस्थापित हुआ
मिश्रित संदर्भ अवधि (स्वास्थ्य /शिक्षा)
(मासिक / वार्षिक आधार पर)

गरीबी रेखा — गरीबी रेखा से ऊपर / गरीबी रेखा से नीचे

- 2011-12 : 270 मिलियन लोग गरीब हैं।
- 2004-05 : 407 मिलियन लोग गरीब (ग्रामीण (41.8%) & शहरी (25.7%)
BPL का 37.2%
- 1993-94 से 2004-05 तक (गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत औसतन प्रति वर्ष 0.74% कम हुआ। और 2004-05 से 2011-12 तक (गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत औसतन प्रति वर्ष 2.4% कम हुआ।

PARMAR SSC

शीर्ष गणना अनुपात / Headcount Ratio : गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के समानुपाती

शीर्ष गणना अनुपात = $\frac{\text{बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}}$

- BPL के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य : छत्तीसगढ़ (39.9%) & झारखण्ड (37%)
- BPL के न्यूनतम प्रतिशत वाले राज्य : गोवा (5.09%) और केरल (7.1%)
  बिहार (33.7%)

5. रंगराजन समिति : 2014

⊙ पोषण संबंधी आवश्यकताओ के भीतर श्रेणियां

Categories - कैलोरी, प्रोटीन, वसा

संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि की बात कही।
(Modified mixed reference period)

↓

साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर उपभोग और व्यय

↓

इस समिति के अनुसार उपभोग और व्यय इकाई

- ग्रामीण क्षेत्र - 972 रु / माह
- शहरी क्षेत्र - 1407 रु / माह

भुगतान संतुलन / Balance of Payment :

देश के वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड

PARMAR SSC

[आयात & निर्यात]

उधार लेना / उधार देना
विदेशी मुद्रा भण्डार मे परिवर्तन

चालू खाता

- सामान / goods
- सेवायें
- ट्रांसफर पेमेंट्स
- प्रेषण / Remittances
  ↓
  भारत पहले स्थान पर
  2nd- मेक्सिको

पूंजी खाता

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- लंबी अवधि का निवेश
- उदा०- वॉलमार्ट ने अधिग्रहण कर लिया। फ्लिपकार्ट की बहुमत हिस्सेदारी

विदेशी संस्थागत निवेश / विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

- अल्पकालिक निवेश
- इसे हॉट मनी भी कहा जाता है।
- उदा०- उधार लेना / देना, परिसंपत्ति की बिक्री / खरीद, NR1 जमा

रक्षा : 74% स्वचालित मार्ग से निवेश, 100% तक निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग से।

CAD: Current account deficit (चालू खाता घाटा)

आयात का मूल्य > निर्यात का मूल्य

GDP का 1.2%

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति

अथवा [RR + गैर- ऋण सृजन CR]

Twin Deficit / जुड़वा घाटा : जब अर्थव्यवस्था मे राजकोषिय घाटा और चालू खाता दोनो होते है।

{CAD + FD}

PARMAR SSC

1991 - भुगतान संतुलन संकट (भारत में)

(Balance of payment crisis) (PM - PV नरसिम्हाराव)

(वित्तमंत्री - मनमोहन सिंह)

LPG Reforms

- Liberalisation – उदारीकरण
- Privatisation – निजीकरण
- Globalisation – वैश्वीकरण

उदारीकरण - विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील।

निजीकरण - सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायों या सेवाओं के स्वामित्व और नियंत्रण को निजी क्षेत्र की संस्थाओं में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया।

वैश्वीकरण - वैश्वीकरण वह आर्थिक सुधार है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करता है।

PARMAR SSC

विदेशी मुद्रा भंडार / Forex Reserves :

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति / Foreign Currency Assets
2. स्वर्ण भंडार / Gold Reserves
3. विशेष आहरण अधिकार / Special drawing Rights (SDR)
   - USD
   - Euro
   - Yen – जापानी मुद्रा
   - Yuan – चीन
   - Pound – ब्रिटेन
4. आरक्षित किश्त स्थिति (Reserve tranche position)

   ↓

   IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के सदस्य देश के कोटा का एक खंड है।

कोटा जितना अधिक होगा, IMF में मतदान शक्ति उतनी ही अधिक होगी।

SDR → इसे पेपर सोना भी कहा जाता है।

IMF के शीर्ष उधारकर्ता -

- 1st - अर्जेंटीना
- 2nd - मिस्त्र
- 3rd - यूक्रेन
- 4th - पाकिस्तान
- 5th - इक्वाडोर

1929 - 30 : अमेरिका में महामंदी

एक अन्य संगठन जो उभरा वह था:

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) ने पुनर्निमाण की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन उसे इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ा।

IMF : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

HQ - वांशिंगटन DC

संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन - ब्रेटन वुड्स सम्मेलन

↓

44 देशों से 730 प्रतिनिधि

- IMF
- विश्व बैंक
  HQ - वाशिंगटन DC

NOSTRO खाता : Our account in your Bank.

" आपकी पुस्तकों पर हमारा खाता है जो हमारे लिए विदेशी मुद्रा है। "

VOSTRO खाता : Your account in our bank.

" हमारी पुस्तकों पर आपका खाता है जो घरेलू मुद्रा मे है।"

FERA : Foreign exchange Regulation Act - 1973

FEMA : Foreign exchange Management Act - 1999

PARMAR SSC

मूल्यह्रास: घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी

मूल्यवृद्धि: घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि

→ मूल्यह्रास की स्थिति में निर्यातकों को लाभ होगा।
- बाजार की ताकतों के कारण
- फ्लोटिंग विनिमय दरें।

अवमूल्यन: यह आधिकारिक मूल्यह्रास है।

पुनर्मूल्यांकन: यह आधिकारिक मूल्यवृद्धि है।

→ सरकारी हस्तक्षेप निश्चित विनिमय दरें।

→ एक निश्चित मुद्रा दर को अक्सर पेग्ड मुद्रा दर कहा जाता है।

लॉरेंज वक्र: धन के वितरण के बारे में बताता 'आय की असमानता के बारे में'

गिनी गुणांक: 0-1

0- Perfect समानता

1- ,, असमानता

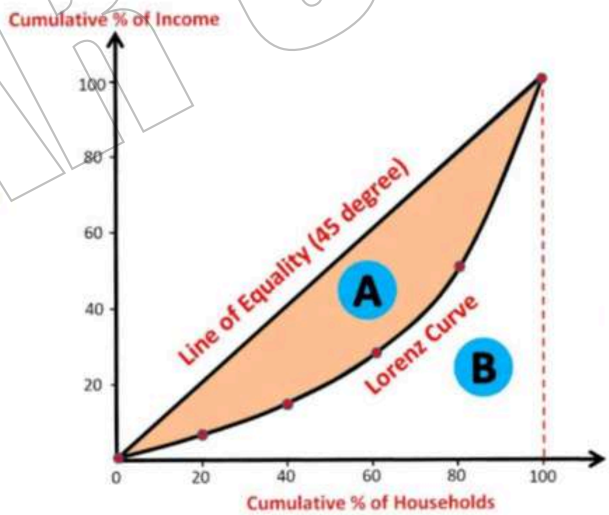

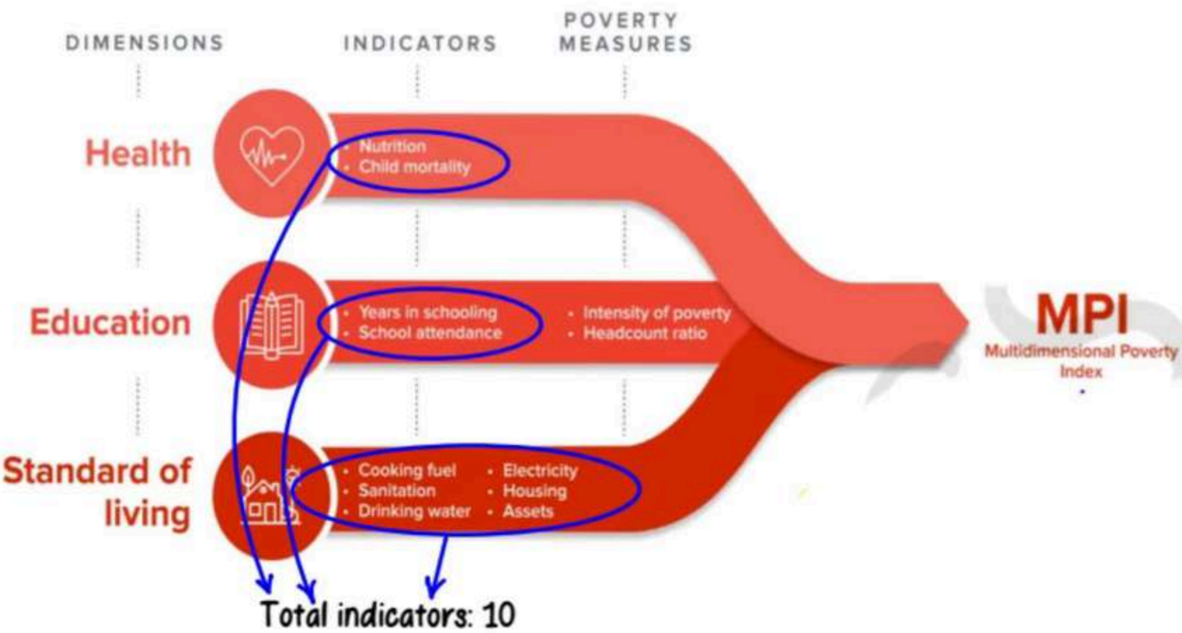

Total indicators: 10

PARMAR SSC

MPI अवधारणा: 2010 UNDP द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) के साथ मिलकर

नीति आयोग द्वारा लॉन्च: (2021) 12 संकेतक → **राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक**

↓

हाल ही में
- 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी
- 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले
- UP में अधिकतम लोग गरीबी से बाहर निकले

उच्चतम MDPI - बिहार

न्यूनतम MDPI - केरल

लोरेंज वक्र - आय या धन के वितरण में असमानता।

फिलिप्स वक्र - मुद्रास्फीति और रोजगार

लाफ़र वक्र - कर दरें और कर राजस्व

- गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को किसी अर्थव्यवस्था में आय असमानता के मापन से जोड़ा जा सकता है।
- यदि निर्यात की कीमतें आनुपातिक रूप से बढ़ें तो मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी होगा।

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति:

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) अतिरिक्त आय के उस हिस्से को संदर्भित करती है जिसे व्यक्ति बचत के बजाय उपभोग पर खर्च करता है। यह मापता है कि आय में एक इकाई की वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है।

PARMAR SSC

$$MPC = \frac{\text{उपभोग में परिवर्तन } \Delta C}{\text{आय में परिवर्तन } \Delta Y}$$

MPC मान : 0-1

'C' से चिन्हित

यदि किसी व्यक्ति की आय में 10,000 की वृद्धि होती है और वह 1000 खर्च करता है.

$$MPC = \frac{1000}{10{,}000} = 0.1$$

स्वायत्त व्यय : वह व्यय जो किसी अर्थव्यवस्था में आय के स्तर की परवाह किए बिना होता है।

↓

यह आय से स्वतंत्र है।

$$C = A + c$$

A = आय स्वतंत्र

c = आय पर निर्भर

C = कुल खपत

Save = 1-C

$$\left\{ \text{व्यय गुणक} = \frac{1}{1-C} \right\}$$

↓

व्यय और बचत के बीच विपरीत संबंध

इंजेक्शन (अर्थव्यवस्था में धन का प्रवेश) :

यह अतिरिक्त निधियां है जो अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती हैं, जिससे कुल व्यय और आय में वृद्धि होती है। वे आर्थिक गतिविधि का विस्तार करने में मदद करते हैं।

PARMAR SSC

प्रकार:

अधिक इंजेक्शन से आर्थिक विकास बढ़ता है।

- निवेश
- सरकारी खर्च

रिसाव (अर्थव्यवस्था से धन का बाहर जाना):

वह निधि है जो चक्रीय प्रवाह से बाहर निकल जाती है, जिससे कुल व्यय कम हो जाता है और आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।

प्रकार:

- बचत
- आयात
- कर

अधिक रिसाव → धीमी आर्थिक वृद्धि

दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, कोई रिसाव नहीं है और कोई इंजेक्शन नही है।

ग्रेशम का सिद्दांत कहता है कि "बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल देता है।"

PARMAR SSC

भारत में पंचवर्षीय योजना

पंचबर्षीय योजना :

स्वतंत्रता से पहले - 1947

" USSR से लिया गया "
↳ 1928, जोसेफ स्टालिन

स्वतंत्रता पूर्व :

- बम्बई योजना (दो भागों में प्रकाशित : 1944 और 1945) और गांधीवादी योजना 1944 में,
- 1945 में जन योजना (भारतीय ट्रेड यूनियन की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति द्वारा), 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना इस दिशा में कदम थे।

  ↳ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन (1934)

कृषि में सुधार :

→ 'जमीन जोतने वाले की जमीन' की नीति
→ भूमि हदबंदी अधिनियम
→ उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज

योजना आयोग - अध्यक्ष- प्रधानमंत्री (राष्ट्रीय बिकास परिषद के भी अध्यक्ष)

स्थापना - मार्च 1950

पहली पंचवर्षीय योजना : 1 अप्रैल 1951 - 1956 (pm - नेहरू)

- कृषि पर विशेष ध्यान
- बांधों की स्थापना
- हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित

{ टारगेट - 2.1 %
{ प्राप्त - 3.6 %
' सफल '

1. भाखड़ा नागल बांध (सतलज)
2. हीराकुण्ड बांध (महानदी)
3. नागार्जुन सागर बांध
(कृष्णा नदी)

मुख्य फोकस - प्राथमिक क्षेत्र

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान
5 IIT स्थापित किए गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना :

1956 - 1961 (pm - नेहरू)

- भारी उद्योगो की स्थापना पर जोर
- तीव्र औद्योगीकरण

IPR - 1956 (2nd) औद्योगिक नीति

राउरकेला : उडीसा (जर्मनी)
दुर्गापुर : पश्चिम बंगाल (UK)
भिलाई : छत्तीसगढ (USSR)

लक्ष्य : 4.5 %
प्राप्त : 4.3 %

'मद्यम रूप से सफल'

मुख्य फोकस - सार्वजनिक क्षेत्र

- भारत का पहला इस्पात संयंत्र - टिस्को (जमशेदपुर, झारखण्ड)

स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75 % आबादी कृषि पर निर्भर थी।

पी. सी. महालनोबिस पर आधारित मॉडल
↓
इनके जन्मदिवस 29 जून पर → सांख्यिकी दिवस
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता

तीसरी पंचवर्षीय योजना : 1961 - 1966 (नेहरू - PM)

- भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतःस्फूर्त बनाना था।
  spontaneous

गाडगिल सूत्र पर आधारित

- भारत-चीन युद्ध - 1962
- भारत - पाक युद्ध - 1965
- हरित क्रान्ति लायी गई।

* PL-480
अनाज आयात (USA से)

उद्देश्य : 5.6 %
प्राप्ति : 2.8 %
'असफलता'

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) - 14 जनवरी 1965
- CACP - 1 जनवरी 1965
- IDBI - 1 जुलाई 1965
- UTI - 1963

2 प्रधानमंत्री :
- जवाहर लाल नेहरू
- लाल बहादुर शास्त्री → 'जय जवान जय किसान' नारा दिया
  (जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में गया।)

योजना अवकाश : 3 साल "वार्षिक योजना"

1966-1969 (नयी कृषि योजना)

हरित क्रांति

- पहला चरण: 1960-1970 के मध्य
- दूसरा चरण: 1970 के मध्य

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना: 1969-1974 (pm- इंदिरा गांधी)

- उद्देश्य- स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति
- परिवार योजना / Family planning
- 14 बैंको का राष्ट्रीयकरण

भारत-पाक युद्ध - 1971

- पहला परमाणु परीक्षण- स्माइलिंग बुद्धा
- रुद्र स्टलन मॉडल या गॉडगिल सूत्र पर आधारित

लक्ष्य : 5.7 %
प्राप्ति : 3.3 %
बडी असफलता

पांचवी पंचवर्षीय योजना: 1974-1978 (pm- इंदिरा गांधी)

- डी.पी. धर मॉडल पर आधारित

→ गरीबी उन्मूलन (इंदिरा गांधी) के साथ आत्मनिर्भरता

- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974)
- 20 सूत्री कार्यक्रम (1975)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना (1975, अक्टूबर 2)

लक्ष्य- 4.4 %
प्राप्ति- 4.8 %
(थोड़ी सफलता)

पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य:

1. विकास: सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि
2. आधुनिकीकरण: नई तकनीक का परिचय + महिला श्रम शक्ति की भागीदारी
3. आत्मनिर्भरता: अंतर्मुखी रणनीतियाँ
4. समानता: सभी के लिए विकास

5 वर्षीय योजना न केवल पाँच साल की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती हैं, बल्कि यह भी बताती है कि 20 साल की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को 'परिप्रेक्ष्य योजना' कहा जाता है।

अनवरत योजना - 1978-80 (PM- मोरारजी देसाई - जनता सरकार)

- रोजगार पर विशेष ध्यान

प्रतिपादन - गुन्नार मिर्डल
लागू करने का श्रेय - डी.टी. लकड़ावाला

छठी पंचवर्षीय योजना : 1980-1985 (PM - इंदिरा गांधी)

- गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया।
- आर्थिक विकास
- प्रौद्योगिकी का आधुनीकरण

लक्ष्य - 5.2%
प्राप्ति - 5.7%

- नाबार्ड की स्थापना - 1982

TRYSEM :	स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण
IRDP :	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
NREP :	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

- ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) - 15 अगस्त 1983
- राष्ट्रीय आय

सातवी पंचवर्षीय योजना : 1985 - 1990 (pm - राजीव गांधी)

लक्ष्य : खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि, उत्पादकता व रोजगार अवसरो मे वृद्धि पर विशेष ध्यान।

जवाहर रोजगार योजना 1989

लक्ष्य : 5 %
प्राप्ति : 6 %
अधिक सफलता

- Hindu Rate of growth → 1978
  हिन्दू वृद्धि दर
  → प्रो. राज कृष्णा
  1960 - 1980 → धीमी आर्थिक वृद्धि

वार्षिक योजना : 1990 - 1992

- 1991 - भुगतान संतुलन संकट / Balance of Payment Crisis
  → IMF

1991 - 1992
- L - Liberalise / उदारीकरण
- P - निजीकरण / Privatisation
- G - वैश्वीकरण / Globalisation

आठवी पंचवर्षीय योजना : 1992 - 1997

(pm - PV नरसिम्हा राव)

- नई सांकेतिक नीति
- आर्थिक और राजकोषीय सुधार
- सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से मे पतन
- लाइसेंस राज खत्म

लक्ष्य : 5.6 %
प्राप्ति : 6.8 %
अधिकतम सफलता

→ आठवीं योजना 1990 में केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण शुरू नहीं हो सकी और वर्ष 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद आठवीं योजना को अंततः 1992 में शुरू किया गया।

→ 1990 तक देश की लगभग 65% जनसंख्या कृषि में ही रोजगार प्राप्त करती रही।
1950 से 1990 के बीच कृषि द्वारा योगदान किए गए GDP में काफी गिरावट आई, लेकिन उस पर निर्भर जनसंख्या में अधिक बदलाव नहीं हुआ (1950 में 67.5% से घटकर 1990 में 64.9% रह गई।)

नौवीं पंचवर्षीय योजना : 1997-2002 (PM- अटल बिहारी वाजपेयी)

- सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर

लक्ष्य : 6.5%
प्राप्ति : 5.4%

दसवीं पंचवर्षीय योजना : (2002- 2007) (PM- अटल + मनमोहन जी)

लक्ष्य : 8%
प्राप्ति : 7.6%

- सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम
- जूट प्रौद्योगिकी मिशन
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : 2007 - 2012 (pm- मनमोहन सिंह)

- तीव्रतम गति और समावेशी ढंग से निरंतर विकास पर जोर

{ लक्ष्य - 9%
{ प्राप्ति - 8%

बारहवीं पंचवर्षीय योजना : 2012 - 2017 (pm- मनमोहन सिंह)

→ तीव्र, अधिक समावेशी धारणीय विकास
Faster, inclusive & Sustainable growth

योजना आयोग → नीति आयोग → थिंक टैंक

1 जनवरी 2015

→ 2014 में इसे बरखास्त कर दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को त्याग दिया गया।

- रिपोर्ट प्रकाशित करता
- विजन दस्तावेज

'औद्योगिक नीति संकल्प'

(Industrial Policy Resolution)

पहली औद्योगिक नीति - 1948 (डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी)

└ सरकार का एकाधिकार { परमाणु ऊर्जा, रेलवे }
→ लाइसेंस राज शुरूआत

दूसरी औद्योगिक नीति - 1956

- भारत के आर्थिक संविधान के रूप मे जाना जाता।
- औद्योगिक विविधीकरण किया

सूची A - सरकारी क्षेत्र (17)

उदा० : विमानन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, हथियार और गोला बारूद

सूची B - सरकारी + निजी सैक्टर (12)
सूची C - केवल निजी सैक्टर

→ इसे 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

1. सार्वजनिक क्षेत्र - रणनीतिक उद्योग
2. सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र - बुनियादी / प्रमुख उद्योग
3. नियंत्रित निजी क्षेत्र - महत्वपूर्ण उद्योग
4. निजी एवं सहकारी क्षेत्र - अन्य उद्योग

→ 1955 में, ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया।

औद्योगिक नीति संकल्प 1977 :
- 1956 की नीति का विस्तार
- विकेन्द्रीकरण पर मुख्य ध्यान
- लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए।

IPR 1980 : FERA, 1973
MRTP - Monopoly Restrictive Trade Practice

1991 - नई औद्योगिक नीति
- L - Liberalisation/ उदारीकरण
- P - Privatisation/निजीकरण
- G - Globalisation/वैश्वीकरण

- FDI ceiling में बढ़ोत्तरी
- सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश / Disinvestment
- लाइसेंस राज खत्म

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति :

वेतन में कुल वृद्धि का वह अनुपात जो उपभोक्ता बचत के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च करता है।

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta I}$$

ΔC → उपभोग
ΔI → आय

$$0 < MPC < 1$$

$$\text{धन गुणक} = \frac{1}{1 - MPC}$$

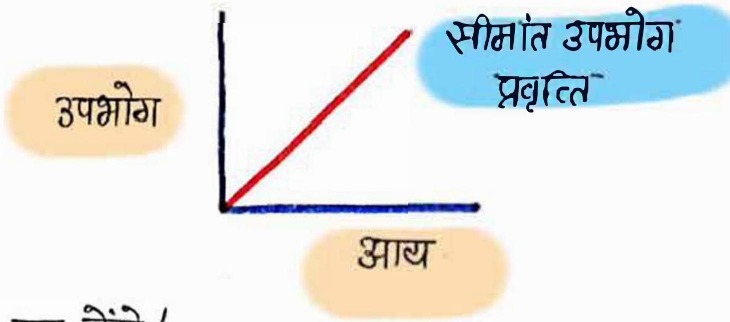

कम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ गुणक कम होंगे।

{ PC महालनोबिस - भारतीय योजना के मुख्य वास्तुकार
पत्रिका - सांख्य